R N No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No : E2/भो.भो./581/2018-2020
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश
वर्ष 21 अंक 05 05 जनवरी 2021

जगत विज़न

बंगाल में ममता की रक्तरंजित राजनीति

बंगाल में किसकी बनेगी सरकार?

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	ममता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	ओंकारनाथ तिवारी
	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 21 अंक 05 05 जनवरी 2021

बंगाल में ममता की रक्तरंजित राजनीति

बंगाल में किसकी बनेगी सरकार?

(पृष्ठ क्र.-6)

- बिना जमींन वाले किसानों की सुध किसे 50
- अधिक कार्बन उत्सर्जन पर कड़ाई जरूरी 52
- शहादत को सलाम-खुदीराम बोस 54
- समूहों ने दी पहचान 56
- Urbanisation Behind Floods 60

Scanned with CamScanner

हाल ही में मैंने जगत विज़न मासिक पत्रिका के दिसम्बर-2020 के अंक का अध्ययन किया। यह अंक देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पर केंद्रित है। अंक में सरदार पटेल की संपूर्ण जीवनी को शामिल किया गया है। सरदार जी के बारे में पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। निश्चित ही समय-समय पर देश के ऐसे महान पुरूषों के विषय में सामग्री प्रकाशित होती रहनी चाहिए ताकि लोग इन महान लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके।

अनंत कुमार वैश्य, दिल्ली

जगत विज़न की मासिक पत्रिका के दिसम्बर 2020 का अंक सरदार वल्लभ भाई पटेल पर केन्द्रित है। यह विशेषांक था। लौहपुरूष के नाम से प्रसिद्ध इस महान विभूति के बारे में पढ़कर मैंने बहुत जानकारी प्राप्त की है। भारत को एक सूत्र में बांधने में जो योगदान सरदार पटेल का रहा है, उसे देश कभी भूल नही सकता है। कैसे और किन परिस्थितियों में उन्होंनें देश की अखण्डता और एकता को बनाए रखा। उनके अतुलनीय योगदान पर प्रकाशित यह अंक संग्रहीय है।

बहादुर मर्सकोले, नागपुर

जगत विज़न मासिक पत्रिका में हमें हर बार कुछ न कुछ समग्री पढ़ने को मिलती है। दिसम्बर 2020 के अंक में हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में पढ़ने को मिला। देश को गढ़ने और बढ़ाने में जिस तरह सरदार पटेल ने अपना योगदान दिया वह अतुलनीय है। ऐसे महान पुरूष के विषय में विशेषांक प्रकाशित कर जगत विज़न ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे अंक हमें पढ़ने को मिलते रहेंगे।

नागेन्द्र तिवारी, रायपुर

मैं जगत विज़न मासिक पत्रिका का नियमित पाठक हूँ। पत्रिका के हर एक अंक का गहराई से अध्ययन करता हूँ। दिसम्बर 2020 के अंक का भी मैंने अध्ययन किया है। यह सरदार पटेल पर केन्द्रित विशेषांक है। सरदार पटेल के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं को समाहित किया गया है। उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े सभी पहलुओं को पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। मेरा मानना है कि समय-समय पर ऐसे महान पुरूषों के विषय में सामग्री प्रकाशित होती रहनी चाहिए। ताकि लोगों को महान पुरूषों के विषय में जानकारी प्राप्त होती रहे।

रवि गुप्ता, बुरहानपुर

पत्रिका में पाठकों की राय का स्वागत है। संदेश भेजकर सुझाव देने के लिये धन्यवाद। आप अपने सुझाव ई-मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ई-मेल द्वारा भेजे गये सबसे अच्छे पत्र को पुरस्कृत किया जायेगा।

संपादक

जगत विज़न

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)

e-mail : jagat.vision@gmail.com, Visit at : www.jagatvision.com

Scanned with CamScanner

कृषि कानूनों पर मचा बबाल

भारत कृषि प्रधान देश है। किसान देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और किसानों की रीढ़ है उनकी उपज और उसके दाम। यदि दाम पर ही सरकार की बंदिशें हावी होने लगे तो देश का किसान सड़कों पर नहीं उतरेगा तो कहां जाएगा। क्योंकि यह किसानों की आजीविका का सवाल है। आज देश के किसानों और बनाए गए कृषि कानूनों पर जो बबाल मचा है वह यही दर्शा रहा है कि अन्नदाता की आजीविका खतरे में है। कानूनों को लेकर किसान भय और शंका में तो सरकार आश्वासन भर देने में लगी हुई है। नतीजा कुछ भी नही निकल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने बाधा मुक्त खेती-किसानी के लिए कृषि उपज व्यापार और वाणिय (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश-2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तीकरण और सुरक्षा) अनुबंध अध्यादेश-2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश-2020 विधेयकों को कानूनी दर्जा दिया है। अभी तक किसान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई मंडियों में ही उपज बेचने को बाध्यकारी थे। अब यह बाधा खत्म हो गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधित करके अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू आदि को इस कानून से मुक्त कर दिया है। नतीजतन व्यापारी इन कृषि उत्पादों का जितना चाहें उतना भंडारण कर सकेंगे। इस सिलसिले में किसानों को आशंका है कि व्यापारी उपज सस्ती दरों पर खरीदेंगे और फिर ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। हालांकि अभी भी व्यापारी इनका भंडारण करके नौकरशाही की मिलीभगत से कालाबाजारी करते हैं। किसान संगठन आशंका जता रहे हैं कि कानून के अस्तित्व में आने के बाद उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाएगी। क्योंकि विधेयक में इस बाबत कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जबकि सरकार ने कहा है कि एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा। सरकार के इस कथन को किसान जुबानी आश्वासन मान रहे हैं क्योंकि एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी विधेयक नहीं देता है।

वर्तमान में आधुनिक खेती और अनाज उत्पादन का गढ़ माने जाने वाले हरियाणा-पंजाब में तभी से अन्नदाता आंदोलन पर उतारू हैं। साफ है किसान लंबी लड़ाई लड़ने को तत्पर दिखाई दे रहे हैं। सरकार भरोसा दे रही है कि किसान मंडियों, आढ़तियों और बिचौलियों से मुक्त हो जाएगा। औद्योगिक घरानों के पूंजी निवेश और तकनीकी समावेशन से पूरे देश में कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। मंडियों का वर्चस्व खत्म कर अनुबंध-खेती लाभदायी होगी। किसानों को पूरे देश में फसल बेचने की छूट रहेगी। इससे किसान वहां अपनी फसल बेचेगा, जहां उसे दाम यादा मिलेंगे। हालांकि पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, केरल और हिमाचल प्रदेश में राय सरकारों ने पहले से ही अनुबंध खेती की सुविधा दी हुई है। इससे किसानों को बहुत यादा फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान कह रहे हैं कि किसान हित मंडी व्यवस्था के सुधार और एमएसपी को कानूनन अनिवार्य बनाने में सुरक्षित हो जाएंगे।

केंद्र सरकार फिलहाल एमएसपी तय करने के तरीके में ए-2 फॉर्मूला अपनाती है। यानी फसल उपजाने की लागत में केवल बीज, खाद, सिंचाई और परिवार के श्रम का मूल्य जोड़ा जाता है। इसके अनुसार जो लागत बैठती है, उसमें 50 फीसदी धनराशि जोड़कर समर्थन मूल्य तय कर दिया जाता है। जबकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है कि इस उत्पादन लागत में कृषि भूमि का किराया भी जोड़ा जाए। इसके बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि जोड़कर समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फसल का अंतरराष्ट्रीय भाव तय करने का मानक भी यही है। यदि भविष्य में ये मानक तय कर दिए जाते हैं तो किसान की खुशहाली बढ़ेगी। एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आयोग ने वर्ष 2006 में यही युक्ति सुझाई थी। किसानों को सबसे बड़ा डर एमएसपी खत्म होने का है। आज देश का किसान सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी फसल जो कोई खरीदे वह केवल एमएसपी पर ही खरीदे। इतनी बात का सीधा सा जबाव देने को तैयार नही है। यदि सरकार की नियत में कोई खोट नहीं है तो कृषि विधेयकों में कोई झोल नही है तो यह कहने में दिक्कत क्या है कि देशभर में एमएसपी अनिवार्य होगा। जाहिर है मंडियां सुबह एमएसपी पर खरीद शुरू करेंगी और किसान की ट्राली तुलने पहुंचेगी तब तक सरकारी खरीद का कोटा पूरा हो जाएगा। बाहर व्यापारी और बड़ी कंपनियां कॉकस बनाकर भाव गिरा देंगे। किसान औने-पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर हो जाएगा। झोल यही है। किसान इसलिए आंदोलन कर रहे हैं।

विजया पाठक

Scanned with CamScanner

बंगाल में ममता की रक्तरंजित राजनीति

बंगाल में किसकी बनेगी सरकार?

Scanned with CamScanner

10 करोड़ जनसंख्या वाले पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ ताल ठोक दी है। बीजेपी के कई दिग्गजों ने बंगाल में रैलियां, सभाएं कर सत्तासीन ममता सरकार की नींव हिला दी है। यह भी पहला अवसर होगा जब बंगाल में बीजेपी सत्ता में आने को करीब दिख रही है। 2018 के बाद बंगाल में बीजेपी ने अपना वोट शेयर भी काफी बढ़ाया है और 2014 में उसे मिले 23.23 फ़ीसदी वोट के मुकाबले 2019 में वह 40.25 फ़ीसदी वोट लेकर आई। जबकि तृणमूल पिछली बार के 39.79 फ़ीसदी वोटों के मुकाबले 2019 में 43.28 फीसदी वोट ही ला पाई। यानी पिछली बार से थोड़े सा ज्यादा। ममता को इस बात का अहसास है कि 2014 की उनकी 34 सीटें 2019 में घटकर 22 हो गई हैं। वह यह भी जानती हैं कि बीजेपी दिन-रात हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी है। इसलिए वह बेहद सतर्क हैं और सक्रिय भी है। यही कारण है कि पिछले कुछ महिनों में ममता बैनर्जी ने हिंदुओं से संबंधित कई अहम फैसले लेकर हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश की है। इससे पहले तो ममता हिंदुओं का पुरजोर विरोध करती आयी है। राज्य में बीजेपी के उदय के साथ ही ममता ने बांग्ला राष्ट्रवाद का कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। खासकर साल 2018 के पंचायत चुनावों और उसके बाद बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिली कामयाबी के बाद उन्होंने इसे तुरुप का पत्ता बना लिया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि बीजेपी जहां ममता पर अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए राज्य के करीब साढ़े पांच करोड़ हिंदू वोटरों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही है, वहीं ममता के पास इसकी काट के लिए बांग्ला राष्ट्रवाद ही प्रमुख हथियार बनाया है। यही वजह है कि ममता अक्सर बंगाली अस्मिता और पहचान का मुद्दा उठाती रही हैं। यह बात भी सच है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी को जोरदार टक्कर दे रही है। टीएमसी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने के बावजूद अंदरुनी कलह और गुटबाजी से जूझ रही है। वर्तमान में ममता सरकार ने राज्य में भय, आतंक, हिंसा, टकराव और दहशत का जो माहौल बनाया है, उससे बंगाल का हर तबका, हर वर्ग, हर समुदाय परेशान हो चुका है। हालांकि यह वही वर्ग, वही समुदाय है जिसने वामदल के 35 वर्ष के शासन के बदले टीएमसी को शासन के लिए चुना था, लेकिन आज की टीएमसी और 10 वर्ष पहले की टीएमसी में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। जो टीएमसी कभी मां, माटी और मानुष के लिए जान देने को उतारू होती थी वह आज सिर्फ शासन पाने या सत्ता में बने रहने के लिए लोगों की जान लेने लगी है। मतलब साफ है कि आज के परिदृश्य में टीएमसी अपने मूलभूत सिद्धांतों से किनारा कर चुकी है या कहे तो तिलांजलि दे चुकी है। टीएमसी का आज सिर्फ, एक ही सिद्धांत है। वह साम, दाम, दंड, भेद से सत्ता में बने रहना। हत्या, हमला, लूट, आतंक उसके हथियार बन चुके हैं। सत्ता की चकाचौंध और परिवार के मोह में बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) प्रमुख ममता बैनर्जी इतनी अंधी हो गई हैं कि उन्होंने पूरे बंगाल को अराजकता, अलोकतांत्रिक, असहिष्णुता और अपराधीकरण में धकेल दिया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं की खुलेआम गुण्डागर्दी चल रही है। इन्हें न कानून का भय है और न ही इन्हें जनता का विश्वास खोने का डर है। ममता बैनर्जी के पहले कार्यकाल को भले ही कुछ ठीकठाक कहा जा सकता है लेकिन वर्तमान कार्यकाल में तो जबसे ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की सरकार में सक्रियता बढ़ी है तबसे बंगाल का बंटाढार प्रारंभ हो गया है। अभिषेक बैनर्जी की सक्रियता का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि ममता बैनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव की पूरी कमान अभिषेक को सौंप दी है।

विजया पाठक

294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बंगाल की सत्तासीन ममता सरकार और बीजेपी में मुख्य मुकाबला होने के आसार भी दिखने लगे हैं। वहीं पिछले 10 साल से राज्य में शासन करने वाली टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) पार्टी की विदाई की आशंका भी पनपने लगी है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह बीजेपी ने बंगाल में अपने पैर जमाए हैं या पसारे हैं उससे तो यही लगता है कि अब बंगाल में बदलाव के दिन आ गए हैं। बदलाव की यह आस बंगालवासियों ने लगाए रखी है। इसके कारण भी कई हैं। क्योंकि वर्तमान में ममता सरकार ने राज्य में भय, आतंक, हिंसा, टकराव और दहशत का जो माहौल बनाया है, उससे बंगाल का हर तबका, हर वर्ग, हर समुदाय परेशान हो चुका है। हालांकि यह वही वर्ग, वही समुदाय है जिसने वामदल के 35 वर्ष के शासन के बदले टीएमसी को शासन के लिए चुना था,

Scanned with CamScanner

बंगाल में 'अभि' मय ममता सरकार

लेकिन आज की टीएमसी और 10 वर्ष पहले की टीएमसी में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। जो टीएमसी कभी मां, माटी और मानुष के लिए जान देने को उतारू होती थी वह आज सिर्फ शासन पाने या सत्ता में बने रहने के लिए लोगों की जान लेने लगी है। मतलब साफ है कि आज के परिदृश्य में टीएमसी अपने मूलभूत सिद्धांतों से किनारा कर चुकी है। या कहे तो तिलांजलि दे चुकी है। टीएमसी का आज सिर्फ, एक ही सिद्धांत है। वह साम, दाम, दंड, भेद से सत्ता में बने रहना। हत्या, हमला, लूट, आतंक उसके हथियार बन चुके हैं।

सत्ता की चकाचौंध और परिवार के मोह में बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) प्रमुख ममता बैनर्जी इतनी अंधी हो गई हैं कि उन्होंने पूरे बंगाल को अराजकता, अलोकतांत्रिक, असहिष्णुता और अपराधीकरण में धकेल दिया है। राज्य में हत्या और हमले तो ऐसे होते हैं जैसे छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं

बीजेपी का दावा

ममता के भय, आतंक और हमले की राजनीति के बीच आम लोगों में बदलाव की आस है। बीजेपी आश्वस्त है कि उसे 200 से अधिक सीटें मिलेगी।

की खुलेआम गुण्डागर्दी चल रही है। इन्हें न कानून का भय है और न ही इन्हें जनता का विश्वास खोने का डर है। ममता बैनर्जी के पहले कार्यकाल को भले ही कुछ ठीक-ठाक कहा जा सकता है लेकिन वर्तमान कार्यकाल में तो जबसे ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की सरकार में सक्रियता बढ़ी है तबसे बंगाल का बंटाढ़ार प्रारंभ हो गया है। अभिषेक बैनर्जी की सक्रियता का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि ममता बैनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव की पूरी कमान अभिषेक को सौंप दी है। जबकि ममता बैनर्जी यह सब जानती हैं कि अभिषेक के कारण टीएमसी के बड़े-बड़े नेता टीएमसी से किनारा कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बताया जाता है कि अभिषेक की घुसपैठ सिर्फ संगठन तक ही सीमित नही है वह सरकार में भी अपनी मनमर्जी चलाता है। यही कारण है कि बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। सरकार का कोई भी फैसला, कोई भी योजना बगैर अभिषेक की मंजूरी से लागू नही की जाती हैं। हम कह सकते हैं कि वर्तमान में अभिषेक बैनर्जी ही सब कुछ है। ममता बैनर्जी एक रबर स्टाम्प बनकर रह गई हैं। टीएमसी में परिवारवाद का हावी होना क्या वाकई में ममता की इच्छा से हो रहा है या ममता की मजबूरी बन गई है।

खैर जो कुछ भी है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस समय टीएमसी

एक देश में बीजेपी के नेता बाहरी कैसे हो सकते हैं?

मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी अपने हर एक भाषण में बीजेपी के तमाम नेताओं को बाहरी बताकर यह जताने की कोशिश करती है कि बंगाल सिर्फ उनकी ही जागीर है। खासकर बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर तो बाहरी व्यक्ति होने के आरोप लगाती रहती हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 11 का इस्तेमाल करके ही मोदी सरकार ने नया नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) बनाया है। इसमें कहा गया है कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अब ममता बैनर्जी को कौन बताए कि पश्चिम बंगाल भी भारत का अभिन्न अंग है और भारत का कोई भी इंसान कही भी जाकर रह सकता है। राजनीति भी इसी का अंग है। फिर बीजेपी के लोग बाहरी कैसे हो सकते हैं। बाहरी व्यक्ति के नारे से ममता खुद अपने आप को भारत से बाहर होने का प्रमाण बता रही हैं।

Scanned with CamScanner

मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी की विफलता के प्रमुख कारण

- मुस्लिमों की हिमायती बताकर हिन्दुओं के प्रति घृणा प्रदर्शित करना।
- बंगाल में भय, आतंक और अलोकतांत्रिक छबि को प्रदर्शित करना।
- परिवारवाद का हावी होना। टीएमसी के प्रमुख नेताओं की अनदेखी करना। भतीजे अभिषेक बैनर्जी को आगे बढ़ाना।
- बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति और स्थानीय बंगालवासियों के प्रति सख्त रूख।
- माओवादियों के प्रति नरम रूख।
- पिछले 10 साल में निवेश का न आना।
- गौ-तस्करी को बढ़ावा देना।
- विकास की अनदेखी करना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना।
- गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा देना।
- केन्द्र की जनहितैषी योजनाओं को लागू न करना।
- बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला, हत्या करवाना।

अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अपने रक्तरंजित राजनीति के रवैये से टीएमसी ने बंगाल में बहुत बढ़ा जनाधार खो दिया है। और इसका अंदाजा हम 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों को देखकर भी लगा सकते हैं। इस चुनाव में बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने सीधे-सीधे 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 02 सीटें मिली थी। मतलब पांच साल में बीजेपी ने अपना जनाधार काफी बढ़ा लिया है। बीजेपी के इस बढ़े हुए जनाधार ने ही ममता की नींद हराम कर दी है। और अपनी कुर्सी भी खिसकती नजर आ रही है। बीजेपी के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए ममता ने ऐसा रास्ता अपनाया है जिसकी कोई कल्पना भी नही कर सकता है। उसने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में आतंक और दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया है, जिससे डरकर बीजेपी खुद पीछे हटने को मजबूर हो जाए। 2018 से अब तक बंगाल में बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं। इन हत्याओं के सभी आरोपी टीएमसी के लोग हैं। मतलब टीएमसी ने जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। लेकिन बीजेपी भी इस दहशत से पीछे नही हटी बल्कि ताकत के साथ और मजबूत होती गई। आज स्थिति यह है कि बंगाल की जनता में टीएमसी के प्रति घृणा और बीजेपी के प्रति

बंगाल में महिलाओं को बहुत आदर मिलता है। यहां की राजनीति में महिलाओं का सम्मान है, लेकिन ममता ने इस आदर, सम्मान का गलत फायदा उठाया। क्रांति को पसंद करने वाले आमजन ठगे गए।

Scanned with CamScanner

सहानुभूति उत्पन्न हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं का क्रम जारी है। हर दिन बंगाल के किसी भी अंचल से ऐसी खबर आ जाती है कि बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। वहीं बीजेपी की सभाओं, रैलियों में हमला आम बात हो गई है। हमला तो बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर कई बार हो चुके हैं। टीएमसी के इस कायरतापूर्ण रवैये का एक ओर जहां टीएमसी के कई दिग्गज नेता विरोध कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर बंगाल में बदलाव की आवाज बुलंद होती जा रही है। आवाज भी ऐसी बुलंद हो रही है कि बंगाल की जनता बदलाव की उम्मीद लगाए बैठी है।

गौरतलब है कि बंगाल में बदलाव की इस सोच के पीछे के चेहरे बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय हैं। जबसे कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में डेरा डाला है तब से यहां पर बीजेपी मजबूत से मजबूत होती होती जा रही है। पहले लोकसभा में परचम लहराया, अब विधानसभा में परचम लहराने को तैयार हैं। जिससे लगने लगा है कि बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बना लेगी। यदि ऐसा होता है तो इसका पूरा श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को जायेगा। जिन्होंने विषम परिस्थितियों में एक ऐसे राज्य में पार्टी को स्थापित किया जहां बीजेपी का जनाधार

अभिषेक बैनर्जी को पसंद है आक्रामक राजनीति। जमीनी राजनीति के बदले लाईम लाईट की राजनीति में बने रहने की छबि। भ्रष्टाचार से अकूत सम्पत्ति अर्जित करना।

ममता के राजशाही पर भारी अभिषेक की तानाशाही

अभिषेक की पत्नि को कस्टम विभाग ने अवैध सोने के साथ पकड़ा था

ये हैं ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी। जो इस समय अपने आपको सुपर सीएम समझ रहे हैं और ममता बैनर्जी भी भतीजावाद के प्रेम में इस कदर फंस चुकी है कि विस चुनाव की पूरी कमान अभिषेक को ही सौंप दी है। अभिषेक ही वह शख्स हैं जिसके कारण आज टीएमसी टूटकर बिखर रही है। धीरे-धीरे छोटे बड़े सभी कद्दावर नेता टीएमसी छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं अभिषेक भारी भ्रष्टाचार पर अकूत सम्पत्ति अर्जित करने में लगे हैं। वैसे भी इन पर भ्रष्टाचार और चरित्र को लेकर पहले कई आरोप लग चुके हैं। अभिषेक पर नामांकन दाखिल करने में गलत शैक्षणिक योग्यता दर्शाने का आरोप है। अभिषेक की पत्नि रूजिरा नरूला को बैंकाक से लौटते समय कस्टम विभाग ने कोलकाता एयरपोर्ट पर दो किलो अवैध सोने के साथ पकड़ा था। मौजूदा ममता सरकार में भी अभिषेक पर बदतमीजी, घपले - घोटाले के कई गंभीर आरोप लगाये जा रहे हैं।

Scanned with CamScanner

अभिषेक के मोह में टूटता टीएमसी का तिलिस्म

शून्य था। बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में कैलाश विजयवर्गीय के योगदान को भुला नहीं जा सकता है।

दरअसल पश्चिम बंगाल का चुनाव कई मायनों में देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला होगा। राष्ट्रीय पटल पर विपक्ष की कद्दावर नेताओं में से एक ममता बनर्जी जहां एक ओर अपनी साख की लड़ाई लड़ेंगी, वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में 42 में से 18 सीटें हासिल करने वाली भाजपा इसे नाक की लड़ाई बना चुकी है। 10 साल पहले तक जो भाजपा पश्चिम बंगाल में अप्रासंगिक मानी जाती थी, वह आज प्रमुख विपक्षी की भूमिका में मजबूती से खड़ी है। वह अब बंगाल पर ममता बनर्जी से पहले 34 सालों तक राज करने वाले वामदलों और उसकी सहयोगी कांग्रेस को अप्रासंगिकता की ओर ढकेलती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में

Scanned with CamScanner

आग से न खेलें मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी-गवर्नर पश्चिम बंगाल

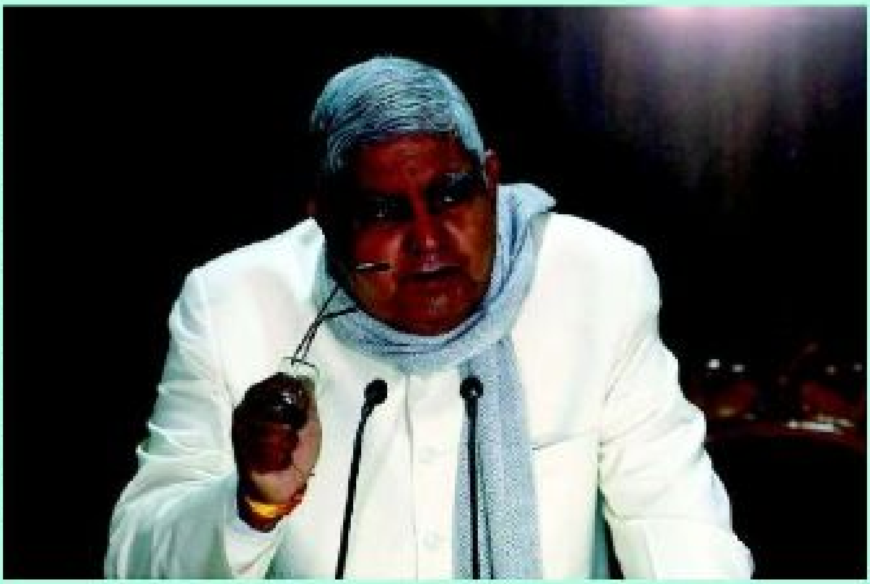

पश्चिम बंगाल के गर्वनर जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सतर्क करते हुए कहा कि आप आग से न खेलें। भारतीय संविधान और कानून-व्यवस्था और बंगाल की संस्कृति का पालन करें। आपने शपथ ली है और संविधान के तहत काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। यदि आप अपने दायित्व से भटकती हैं, तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि वह कुछ ब्यूरो को संदेश देना चाहते हैं कि वह राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं। इससे अपने को बचाएं। दरअसल, डायमंड हार्बर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसे घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। मेरे बार-बार मुख्यमंत्री व प्रशासन को सतर्क करने के बावजूद यह स्थिति हो रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपने संवैधानिक दायित्व का पालन कर रहा हूं और मुख्यमंत्री को संवैधानिक दायित्व का पालन करना चाहिए। सभी को संविधान मानकर चलना होगा। बंगाल में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री के बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया है। कैसे एक जिम्मेदार सीएम, जो संविधान पर, कानून पर विश्वास करती हैं, बंगाल की समृद्ध संस्कृति को प्रतिनिधित्व करती है, वह इस तरह का बयान दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे बयान और वीडियो वापस लेने की अपील की है। एक जिम्मेदार सीएम क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं।

बाहरी के बयान पर जताई आपत्ति- राज्यपाल ने कहा कि यह बयान देना कि ये बाहर के हैं, सही नहीं है। हम भारत वर्ष में हैं। यह बात करना यह अंदरूनी है और यह बाहरी है, बिल्कुल गलत है। जो कानून के शासन पर विश्वास करता है वह ऐसी बातें नहीं करता। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें। भारत की आत्मा एक है। भारत की नागरिकता एक है। यह तो खतरनाक खेल है। कौन बाहरी, कौन अंदरूनी उसे त्याग दें।

रोमांच अभी से उफान पर है। चुनावी हिंसा के लिए पहचानी जाने वाली बंगाल की राजनीति कैडर बेस रही है। शायद इसीलिए वामदलों का गढ़ कहे जाने वाले बंगाल को सत्ता परिवर्तन में 34 साल लग गए। वर्तमान में 10 साल से सत्तासीन पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पास भी समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी नहीं। ममता बनर्जी की छवि लड़ाकू नेता की रही है। ममता बनर्जी ही ऐसी नेता और मुख्यमंत्री रही हैं जो केंद्र, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेती रही हैं, चाहे वह मामला पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी का रहा हो, सीएए-एनआरसी के विरोध का या केंद्र के राज्य के मामलों में हस्तक्षेप का रहा हो। भाजपा वहां खराब कानून-व्यवस्था और राज्य सरकार के मनमाने रवैये को आधार बनाकर लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाती रही है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ममता के विकल्प के तौर पर उसके पास मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है।

पिछले 10 सालों की बंगाल की राजनीतिक हलचल पर गौर करें तो भाजपा के लिए यह आंकड़े उत्साह जगाते हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा खाता नहीं खोल सकी थी, वहीं 2016 में उसे तीन सीटें हासिल हुईं। 2016 में भाजपा का वोट

Scanned with CamScanner

टीएमसी ने कैसे एक उभरते समाजसेवी और राजनेता मनीष शुक्ला को मार डाला

मृतक-मनीष शुक्ला

कोलकाता के बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में मनीष शुक्ला एक चर्चित और जनहितैषी नाम था। मनीष शुक्ला ऐसा शख्स था, जिसकी एक आवाज पर पूरा क्षेत्र खड़ा हो जाता था। मतलब उसकी हर एक समुदाय में इज्जत और सम्मान था। मनीष शुक्ला की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह बैरकपुर क्षेत्र के दो वार्ड 7 और 21 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद चुने गए थे। लेकिन यही लोकप्रियता तृणमूल कांग्रेस को नही पची। परिवारवालों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या टीएमसी के लोगों ने करवाई है। दरअसल 4 अक्टूबर 2020 की सायं मनीष शुक्ला के परिवारवालों पर कहर बनके टूटी थी, क्योंकि उसी दिन मनीष की हत्या हुई थी। दरअसल घटना

शेयर 10.16 फीसदी था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह वोट शेयर 40.25 फीसदी पहुंच गया और उसकी झोली में सांसद की 18 सीटें आ गईं। ममता बैनर्जी की पार्टी का वोट शेयर उससे कुछ ही अधिक 44 फीसदी रहा था। राज्य के लोग बदलाव के लिए बेचैन हैं। बीजेपी बंगाल में पहले से ही तृणमूल कांग्रेस पर अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने और सरकार प्रायोजित आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाती रही है। इनके अलावा भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोपों के बूते ही उसने बीते

Scanned with CamScanner

मृतक मनीष शुक्ला के पिता डॉ. चन्द्रमणि शुक्ला एवं माता उर्मिला शुक्ला से बातचीत करती हुई जगत विजन मासिक पत्रिका की संपादक विजया पाठक

कुछ इस प्रकार थी। 04 अक्टूबर को मनीष शुक्ला बैरकपुर क्षेत्र के सांसद अर्जुन सिंह के साथ मीटिंग करके घर लौट रहे थे। इसी बीच मनीष के पास फोन आया कि टीटागढ़ थाना के पास आग लगी है। मनीष यह बात सुनकर घर न जाकर आग वाली जगह पर गए। इसी बीच दो मोटरसाइकिल मनीष का पीछा कर रही थी। जैसे ही मनीष स्पॉट पर पहुंचे। गाड़ियों में सवार 5-6 लोगों ने मनीष पर धड़ाधड़ गोलियों की बरसात कर दी। इतना ही नही शूटरों ने लौटकर उनके सिर में गोली मारी। बताया जाता है कि कोई 20-25 गोलियां मारी गई थी। यह कोई सायं के 7 बजे हुआ था। जिस स्थान पर मनीष को गोलियां मारी गई उस स्थान से थाना कोई 100 मीटर की दूरी पर था, लेकिन घटना घटने के 40 मिनट तक थाने से कोई पुलिस वाला नही आया। मनीष की इस तरह बेरहमी से हुई हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। लोगों में आक्रोश भी था और मनीष के प्रति प्रेमभाव भी था। बताया जाता है कि इस मर्डर की खबर पुलिस प्रशासन को भी थी। गौरतलब है कि जिस स्थान पर मनीष की हत्या हुई थी वह स्थान मनीष का गढ़ था। वहां के लोग मनीष को फरिश्ता मानते थे। हत्या करने और करवाने वालों में यह स्थान भी इसीलिए चुना था कि ताकि लोगों में भय और आतंक का संदेश जाए।

मनीष केवल राजनेता भर नही था। वह एक नरम दिल समाजसेवी भी था। सृष्टि नामक स्वयंसेवी संस्था भी चलाता था। इस एनजीओ के माध्यम से मनीष गरीब, असहाय लोगों की खूब मदद करता था। कोरोनाकाल में इस संस्था द्वारा 75 दिन तक 12-14 रसोई चलती थी, जहां मददगारों को मुफ्त में भोजन दिया जाता था। प्रत्येक दिन कोई 10-12 हजार लोगों का भोजन होता था। सृष्टि के माध्यम से मनीष 2 हजार गरीब बच्चों को पढ़ाता था। यह सब मनीष पार्टी से हटकर करता था। यही कारण था कि वह पूरे क्षेत्र में भी नही पूरे कलकत्ता में

लोकसभा चुनावों में अपनी सीटों की तादाद पिछली बार के दो के मुकाबले बढ़ाकर 18 तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल की थी।

बीजेपी के लिए बिहार से ज्यादा अहमियत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की है। गृहमंत्री अमित शाह बिहार में तो एक बार भी नहीं गए लेकिन बंगाल के कई दौरे कर लिए हैं। अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत भी उस आदिवासी-बहुल बांकुड़ा ज़िले से की जहां बीते पंचायत और लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था। झारखंड से सटे इस आदिवासी-

Scanned with CamScanner

लोकप्रिय था। उसके कार्यों की सभी ओर चर्चा होती थी। सृष्टि संस्था में सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों की मदद होती थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी को लेकर काम होते थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि हमने एक महान कर्मवीर को खो दिया है। आज सृष्टि का संचालन भी बंद है और लोगों की सहायता भी बंद है।

हालांकि यह भी नही है कि मनीष को अपनी हत्या का डर नही था। उसे इस बात का भय काफी पहले से ही सताने लगा था। यही वजह थी कि उसने परिवार वालों की जानकारी के बगैर 10 सितम्बर 2020 को राज्यपाल को एक पत्र लिखा था, जिसमें मनीष ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है। राज्यपाल ने डीआईजी को पत्र लिखा कि मनीष शुक्ला की जान को खतरा है। पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके बाद 26 सितम्बर 2020 को मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के नाम से राज्यपाल के पास एक पत्र आया कि मनीष शुक्ला को किसी प्रकार का खतरा नही है। पुलिस सुरक्षा देने की जरुरत नही है। उसके 10 दिन बाद ही मनीष की हत्या हो जाती है। आज तक इस मर्डर में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मामला सीआईडी के पास है।

यह भी बताया जाता है कि नगर निगम मुनसी पुट्टी में दो चैयरमेन प्रशांतो चौधरी और उत्तमदास थे, जिन्हें मनीष ने ही चैयरमेन बनबाया था। इन दोनों ने भारी भ्रष्टाचार किया था और मनीष को यह बात बहुत गलत लग रही थी। चैयरमेन और मनीष के मनमुटाव काफी बढ़ गए थे। यहां तक कि एक भरी सभा में चैयरमेन ने कहा था कि ममता दीदी का इशारा मिल जाए तो हम मनीष को मार देंगे।

दरअसल मनीष शुक्ला ने राजनीति की शुरूआत तृणमूल कांग्रेस से की थी। मनीष क्षेत्र में टीएमसी का काउंसलर था। कुछ महिनों पहले ही वह टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ था और जिला कमेटी का सदस्य था। मनीष का टीएमसी छोड़ने से टीएमसी को पांच विधानसभा सीटें गंवाने का खतरा था। क्योंकि उसका बैरकपुर लोकसभा की कुल 7 विधानसभा सीटो में से 5 पर काफी प्रभाव था।

प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही मनीष को टीएमसी में रहते हुए वाई कैटेगेरी की सुरक्षा मिली हुई थी। टीएमसी से हटते ही यह सुरक्षा भी हटा ली गई थी। टीएमसी छोड़ने का कारण भ्रष्टाचार था। आज मनीष के माता-पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वह सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। वह ममता सरकार को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि मनीष को मारकर ममता सरकार ने बहुत बड़ी भूल की है। इनका कहना है कि सरकार के मंत्री कह रहे है कि यह मामूली घटना है। इसमें टीएमसी का कुछ लेना देना नही है। परिवारवालों का कहना है कि हमारे बेटे को मारने की 5 करोड़ की सुपारी दी गई थी। और बगैर सरकार के संरक्षण के इतनी बड़ी घटना नही हो सकती। मनीष को मरवाने में सरकार का पूरा-पूरा हाथ है। हमारा एक ही लड़का था। उसके दो बच्चे हैं। उसका कौनसा अपराध था, जो उसे जान से मार दिया। वह कुछ भी गलत काम नही करता था। वह तो गरीबों की दिन-रात सेवा करता था। लोगों के घर चूल्हा जलवाता था। हमें भी मार दिया जाता। घटना का जिक्र करते हुए वह बताते हैं कि घटना के पांच दिन पहले से ही गार्ड को धमकी मिलती थी कि तुम रास्ते से हट जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। माता-पिता का कहना है कि हमें पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नही है। हमारी मदद करने का भरोसा नही है। क्षेत्र में लोकप्रियता का जिक्र करते हुए पिता रोते हुए बताते हैं कि मनीष की शवयात्रा में हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। लोगों ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था। वह लोगों की काफी मदद करता था। मैं भी पढ़ना चाहता हूं कार्यक्रम में 2 हजार बच्चे पढ़ते थे। भोलानंद वृद्धाश्रम में 70-80 बुजुर्गो को खाना खिलाता था और सबका साल भर मे एक दिन जन्मदिन मनाता था। माता-पिता कहते हैं कि जब हिन्दू-मुस्लिम के त्यौहार एक साथ पड़ते तो पुलिस प्रशासन मनीष की सहायता लेते थे, ताकि किसी भी प्रकार का सामाजिक सौहार्द न बिगड़े। पुलिस वाले कहते थे कि मनीष तुम संभाल लेना। मनीष भी शांति से त्यौहार मनवा लेता था। वह बहुत निडर था। पिता ने बताया कि जब बैरकपुर विधायक शीलभद्र दत्तो को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने पत्रकार वार्ता कर ऐलान किया कि वह अब कभी भी टीएमसी से चुनाव नही लड़ेंगे। यह बहुत गलत काम हुआ है। हमने बंगाल का भविष्य खो दिया है।

बहुल इलाके में उन्होंने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर फूल-माला चढ़ाई। वहां उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत की, दोपहर में एक आदिवासी के घर ज़मीन पर बैठकर भोजन किया और उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के आधार पर भाजपा को 120 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। शायद शाह का दावा उस पर ही आधारित है। ऐसे दावों पर भरोसा कर कशमकश में रहे कुछ वोटर भाजपा के पाले में जा सकते हैं।

Scanned with CamScanner

टीएमसी का सिमटता कुनबा- एक समय था जब केन्द्र की राजनीति में भी तृणमूल कांग्रेस का रूतबा हुआ करता था। एनडीए की अटल बिहारी वाजेपेयी सरकार से लेकर यूपीए की मनमोहन सरकार में भी टीएमसी हिस्सेदार हुआ करती थी। मतलब टीएमसी एक बहुत जिम्मेदार और प्रभावी पार्टी हुआ करती थी। हिस्सेदारी के बदले कभी ममता बैनर्जी तो कभी टीएमसी के सांसद केन्द्र में मंत्री भी बनते थे। लेकिन टीएमसी के बदलते रवैये और अपने खोते मूल सिद्धांतों के चलते आज उसका कुनबा और जनाधार दोनों कम होते जा रहे हैं। यहां तक कि टीएमसी के जनाधार और प्रमुख रणनीतिकार मुकुल राज्य टीएमसी से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज की स्थिति में असंतुष्टों में इतने नाम हैं कि गिनती नही लगाई जा सकती है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव आते-आते करीब-करीब सभी लोकप्रिय टीएमसी नेता टीएमसी छोड़ चुके

टीएमसी कार्यकर्ताओं ने राधारानी नासको को सिर में मारी गोली

कलकत्ता के चौकराजू मोहल्ला की रहने वाली बीजेपी कार्यकर्ता राधारानी नासको को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सिर के पीछे चैथी में गोली मारकर जान लेने की कोशिश की गई थी। राधारानी का कसूर भर इतना था कि वह बीजेपी की कार्यकर्ता थी। आज राधारानी इस हमले से इतनी दहशत में है कि वह ससुराल न जाकर मायके में रहने को मजबूर है। हमला होने के बाद जब राधारानी ने केस दायर किया तो अब टीएमसी के लोग केस वापिस लेने की धमकियां दे रहे हैं। इसी डर और दहशत में पूरा परिवार रह रहा है। परिवारवालों को काम तक नही करने दे रहे हैं। इस हमले के असली अपराधी पंचूलाल नश्क को पुलिस ने आज तक नही पकड़ा है। बाकी पांच लोगों को पकड़ लिया है। राधारानी बताती हैं कि उसके पति अरूण नश्क पर भी हमला हो चुका है। जो बीजेपी के मंडल कमेटी का सदस्य है। राधारानी कहती हैं कि हमारे बूथ में 1300 लोग और पूरे मंडल में 40-50 हजार लोग रहते हैं। इस मंडल में ज्यादातर बीजेपी के लोग हैं। यही कारण है कि टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर मंडल में दहशत का माहौल बनाना चाहती है। इससे लोग डर के कारण बीजेपी में न जाए। वह कहती है कि चुनाव के समय खतरा और बढ़ जाता है। पुलिस हमारी बिल्कुल भी मदद नही करती है। राधारानी सुझाव देती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पुलिस नहीं बल्कि मिलेट्री लगनी चाहिए। पूरा मंडल छावनी बनना चाहिए। तभी यहां पर वोटिंग हो सकती है क्योंकि बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण टीएमसी यहां वोटिंग ही नही होने देती है। हमारे 3 अंचलों कुलिकदाड़ी, पनाकुंअर और आमगछिया में तो वोट ही नही डलते हैं। पिछले चुनाव में भी हमें वोट नही डालने दिया। बूथ केप्चरिंग होती है। अब राधारानी को चिंता है कि वह कभी ससुराल जा पाएगी कि नही। क्योंकि जब तक केस चलेगा इसकी जान को खतरा बना रहेगा।

राधारानी से बात करती हुई जगत विज़न मासिक पत्रिका की संपादक विजया पाठक

Scanned with CamScanner

चार बार अटैक हुआ बबलूदास पर

कोलकाता के डायमंड हरबोर लोकसभा क्षेत्र के 4 नम्बर के मंडल सभापति बबलूदास पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 4 बार अटैक किया है। बबलूदास पर अटैक इसलिए हुआ कि क्योंकि वह बीजेपी का कार्यकर्ता है। बबलूदास बेहद गरीब और मेहनत मजदूरी कर अपनी रोजी-रोटी चलाता है। बबलू जिस जगह पर रहता है वहां क्रिश्चन और हिन्दु समुदाय के लोग निवास करते हैं। यह पूरी बस्ती झुग्गीबस्ती है। अपने ऊपर हुए एक हमले का जिक्र करते हुए बबलू बताते है कि वह घर पर अपने परिवार के साथ था। इसी बीच हमारे घर में टीएमसी के कोई 30 कार्यकर्ता आए और मुझ पर डंडों से हमला कर दिया। इस हमले मे मैं बुरी तरह घायल हो गया था। शुक्र है कि मेरी जान बच गई। मैंने यहां के स्थानीय टीएमसी विधायक दिलीप मुंडे को पूरे हमले का वीडियो भेजा। बावजूद उसके हमलावरों पर कोई कार्यवाही नही हुई। बबलू बताता है कि हमारे मंडल में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें शासकीय राशन की दुकानों से राशन नही मिलता है। जबकि हम भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं। साथ ही किसी भी शासकीय योजना का लाभ नही मिलता है। जबकि टीएमसी कार्यकर्ताओं को पूरा लाभ मिलता है। यहां तक कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता स्थानीय बाजार में दुकानें भी नही खोल सकते हैं। यदि खोल भी लें तो टीएमसी के लोग हमें मारते हैं, धमकाते हैं। यहां के बाजार में टीएमसी के लोग उगाही भी करते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों की कोई सुनवाई नही होती है।

बबलूदास से बातचीत करती हुई जगत विजन मासिक पत्रिका की संपादक विजया पाठक

होंगे। टीएमसी का कुनबा प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इन कद्दावर नेताओं के असंतुष्टों होने और टीएमसी छोड़ने का बहुत बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना होगा। आज भले ही ममता बैनर्जी इस बात से बेफिक्र लग रही हो लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वह बहुत बड़े वोट बैंक को साधते आ रहे हैं। टीएमसी केवल ममता बेनर्जी के बदौलत नही है बल्कि टीएमसी को गढ़ने में और बढ़ाने में कई नेताओं ने खून पसीने से सींचा है।

ममता सरकार में कानून व्यवस्था ऐसी है कि टीएमसी के खिलाफ किसी की भी एफआईआर नहीं लिखी जाती।

परिवारवाद में कैसे कमजोर हुई पार्टियां- राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद से कमजोर हुई हैं। इतिहास गवाह है कि जब-जब राजनीतिक पार्टियों ने परिवारवाद को अपनाया है उनका पतन होता गया है। इसका सबसे सटीक उदाहरण कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पर हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। आरोप इसलिए भी

Scanned with CamScanner

टीएमसी में शामिल नही हुआ तो आमिर अली खान को मार डाला

मृतक आमिर अली खान के भाई साबिर अली खान से बातचीत करती हुई जगत विजन मासिक पत्रिका की संपादक विजया पाठक

वार्ड नम्बर 12, कालीपुर, अरमबाग निवासी 21 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता आमिर अली खान को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इसलिए मार दिया कि वह टीएमसी में शामिल नही हुआ था। कालीपूजा (दीपावली) के दिन सुबह 6 बजे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीच चौराहे पर हमला किया। हमले में उसकी मौत हो गई। आमिर युवा कार्यकर्ता था और क्षेत्र में काफी एक्टिव था। आमिर पहले सीपीएम में था, फिर टीएमसी में गया और अब बीजेपी में था। हमला करते समय हमलावर यही कह रहे थे कि बीजेपी के लिए काम करेगा। मृतक आमिर के भाई साबिर अली का कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ता खून-खराबे पर उतर आए हैं। इस हत्याकाण्ड में टीएमसी के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे, जो सभी मुस्लिम थे। तीन महीने में सभी की जमानत हो गई है और आज भी यही पर घूम रहे हैं। साबिर ने बताया कि आमिर की शादी हो गई थी और उसका 1 बच्चा है, अब पत्नी और बच्चा मुर्शीदाबाद चले गए हैं। उसने बताया कि आमिर काफी एक्टिव कार्यकर्ता था। वह कई लोगों को बीजेपी में लाया था। शायद इसलिए टीएमसी के लोगों ने उसे मारा है। उसकी हत्या पब्लिक के सामने हुई थी।

सत्य है कि कांग्रेस के जन्म से लेकर आज तक परिवारवाद से अलग नही हो पायी है। इसी मोह के कारण आज कांग्रेस गर्त में जा गिरी है। कांग्रेस की वर्तमान समय में जो स्थिति है वह पुत्रमोह के कारण ही है। बावजूद उसके पार्टी मोह को नही छोड़ पा रही है। क्या तृणमूल कांग्रेस भी इसी रास्ते को अपनाना चाहती है। ममता बैनर्जी भी भतीजावाद के चलते टीएमसी की दुर्गति की चिंता नही कर रही है। जबसे अभिषेक बैनर्जी ने टीएमसी में सक्रियता बढ़ाई है तबसे ही पार्टी का पतन प्रारंभ हुआ है। परिवारवाद का सीधा असर पार्टी के उन नेताओं पर पड़ता है जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में दिन-रात एक किया था। और जब बात सत्ता-शासन की आती है तो इन नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। टीएमसी में यही हो रहा है। वर्चस्व की इस लड़ाई में वह नेता असंतुष्ट हो गए जिन्होंने पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां परिवारवाद

ममता सरकार में अब तक हो चुकी हैं 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या

Scanned with CamScanner

के कारण पार्टियां नुकसान झेलने को मजबूर हुई हैं। समाजवादी पार्टी में भी ऐसा ही हुआ था।

सीएए-एनआरसी फिर बन सकता है मुद्दा- सीएए-एनआरसी बंगाल में यह मुख्य मुद्दों में शामिल हो सकता है। बांग्लादेशी अप्रवासियों की बड़ी तादाद होने के कारण यह मुद्दा बंगाल की राजनीति को बेहद प्रभावित करता रहा है। ममता बनर्जी शुरू से इसके विरोध में रही हैं, जबकि भाजपा इसे हर हाल में बंगाल में लागू करना चाहती है। इस मुद्दे पर वोटों के ध्रुवीकरण की भी कोशिश होगी, जिसमें इस चुनाव में बड़ी भूमिका ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी नजर आने लगी है। ओवैसी ने साफतौर पर बंगाल चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों की

10 दिसम्बर 2020 को बीजेपी की एक सभा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के काफिले पर हमला बोला था। इस हमले में कैलाश विजयवर्गीय घायल हुए थे। वहीं और भी कई बीजेपी नेता घायल हुए थे। ईट, पत्थरों से गाड़ियों पर हमला बोला था। यह घटना अभिषेक बैनर्जी के संसदीय क्षेत्र में हुई थी और टीएमसी के 10 हजार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा था।

04 राजनीतिक लोगों के मर्डर हो चुके अरमबाग में

अरमबाग के बीजेपी जिला अध्यक्ष विमान घोष का कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 से अधिक सीटें जीतेगी। अमरबाग जिले की सभी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी को बहुत बड़ा माफिया बताया है। ममता के दो हाथ हैं एक अभिषेक बैनर्जी और दूसरा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बंगाल में बिजनेस करने आया है। 500 करोड़ रुपये ममता बैनर्जी देगी और वह बंगाल से 2 हजार करोड़ रुपये लेकर जाएगा। विमान घोष का कहना है कि अरमबाग क्षेत्र में कुल 8 मर्डर हुए हैं, जिसमें राजनीतिक मर्डर हैं। एक हत्या तो टीएमसी ने टीएमसी नेता की है। काशीनाथ घोष, सुदर्शन प्रमाणिक, गणेश राय बीजेपी के नेता थे। सभी मर्डर में टीएमसी के लोगों का हाथ था।

बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतेगी बीजेपी-कैलाश विजयवर्गीय

पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से अधिक सीटें जीतेंगी। विजयवर्गीय पिछले कई सालों से बंगाल में डेरा डालकर राज्य में पहली बार बीजेपी को स्थापित करने में जुटे हैं। वर्तमान समय में बंगाल में बीजेपी जो मजबूत स्थिति है उसका श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को भी जाता है। विजयवर्गीय के प्रभारी रहते हुए ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर राज्य की टीएमसी सरकार की नींव हिला दी है। यही कारण है कि आज बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी का हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में ही आज टीएमसी के कई कद्दावर नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तमाम मुसीबतों को झेलते हुए वह बंगाल मे बीजेपी की सरकार बनाने में जुटे हैं। ममता सरकार द्वारा पिछले कुछ महिनो से बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं पर हमले कराये जा रहे हैं। यहां तक कि कैलाश विजयवर्गीय पर भी कई हमले हो चुके हैं। बावजूद उसके वह अडिग है और ममता सरकार के सामने पूरी ताकत के साथ डटे हैं। दरअसल ममता बैनर्जी नही चाहती है कि बंगाल में बीजेपी खड़ी हो। ममता सरकार की गुण्डातगर्दी, आतंक और कुप्रशासन से पूरा बंगाल त्राहिमाम है और बंगाल के लोग चाहते हैं कि बंगाल से टीएमसी की सरकार हट जाए। पिछले 10 साल में ममता सरकार ने बंगाल को भय, आतंक का अड्डा बना दिया है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि ममता सरकार के इशारे पर 2018 से अब तक 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी हैं। वही 4 पत्रकारो की भी सरकार ने हत्या करवायी है। बंगाल मे अपनी जिम्मेदारी को लेकर उनका कहना है कि इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। हाईकमान जो आदेश देगा, मैं उसका पालन करूंगा। नागरिकता कानून को लेकर उनका कहना है कि चुनाव के पहले बंगाल में इसे लागू करेंगे। वहीं ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के विषय में उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी प्रतिदिन भ्रष्टाचार से 50 करोड़ रूपये का कलेक्शन कर रहे हैं। चारो ओर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़क किनारे लगी लाईटो से ही कोलकत्ता में 100 करोड़ का घोटाला हुआ। वहीं रंगाई पुताई मे भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। बंगाल में वोटिंग नही होने के विषय मे पूछने पर विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार हमारा फोकस इस बात को लेकर रहेगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक वोटिंग हो। इसके लिए अधिक संख्या मे सेंट्रल फोर्स लगाएंगे। लोगो मे भय कम करेंगे। वही टीएमसी से बीजेपी मे आ रहे नेताओं को विषय मे उनका मानना है कि इससे बीजेपी मजबूत हो रही है और टीएमसी कमजोर। विजयवर्गीय का मानना है कि हरियाणा से ज्यादा विश्वास है कि बंगाल मे बीजेपी बड़ी ताकत से साथ आ रही है।

डेमोग्राफी काफी कुछ बिहार के सीमांचल से मिलती-जुलती है, जहां एआईएमआईएम पांच सीटें जीतने में कामयाब रही है। इस जीत से उत्साहित ओवेसी बंगाल के चार-पांच जिलों में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन ने जिस तरह ओवैसी को हल्के में लेने की भूल की, उससे टीएमसी सावधान तो जरूर हुई होगी लेकिन देखना यह होगा कि ममता इसकी कोई काट

Scanned with CamScanner

बंगाल के लोग चाहते हैं बदलाव-मुकुल रॉय

पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुकुल राय का बड़ा नाम है। बंगाल के लोग इन्हें दादा के नाम से पुकारते हैं। मुकुल राय ही वह शख्स हैं जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी थी। टीएमसी में रहते हुए यह रेल मंत्री भी रह चुके हैं। मुकुल राय का नाम कद्दावर और लोकप्रिय नेताओं में लिया जाता है। वर्तमान में मुकुल राय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वे बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने में कैलाश विजयवर्गीय के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बंगाल की राजनीति और ममता सरकार को लेकर उन्होंने खुलकर बात की। मुकुल राय का कहना है कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। क्योंकि पिछले 10 साल में ममता शासन ने बंगाल को कंगाल और भय, आतंक का राज्य बना दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवेश जैसी बुनियादी जरुरतों से बंगाल बेहाल हो चुका है। चारों ओर ममता सरकार से लोग परेशान हैं। इनका मानना है कि अब बंगाल के लोगों को ममता सरकार पर विश्वास नही

खोज पाती हैं या नहीं, क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण का डर उन्हें भी सता रहा। भाजपा ने ममता की छवि को अल्पसंख्यकों के प्रति खास झुकाव रखने वाली नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। इस छवि को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की बंदिशों के बावजूद बंगाल में दुर्गापूजा के दौरान कोई खास पाबंदी नहीं लगाई गई और कई पूजा पंडालों का उन्होंने उद्घाटन भी किया। ऐसे में उत्तर बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, बीरभूम व दक्षिण बंगाल के साउथ

ममता की माँ, माटी और मानुष की सोच पर भारी भय, आतंक, हत्या और हमला

24 परगना जैसे जिलों में जहां अल्पसंख्यकों की आबादी निर्णायक है, में ममता बनर्जी की क्या रणनीति होती है यह देखना रोचक होगा। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में 18 में से 7 सीटें भाजपा को उत्तर बंगाल से मिली थीं।

गोरखालैंड का मुद्दा गले की फांस- कुछ माह पहले 2017 से भूमिगत चल रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विमल गुरुंग ने कोलकाता में अचानक एनडीए से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी। जीजेएम वर्ष 2009 से एनडीए का हिस्सा रही है और

Scanned with CamScanner

है। बीजेपी ही एक ऐसी सिंगल पार्टी है जो बंगाल में बदलाव कर सकती है। बीजेपी भी अपनी दम खम के साथ टीएमसी को उखाड़ फेंकने में लगी है। टीएमसी के विषय में मुकुल दा का कहना है कि टीएमसी का जब गठन हुआ था तब इसके 12 मूल उद्देश्य थे लेकिन अब ये मूल उद्देश्य खो चुके हैं। टीएमसी अलोकतांत्रिक हो गई है। बंगाल में लोकतंत्र बचा ही नही है। यही कारण है कि मैंने टीएमसी का साथ छोड़ा है। टीएमसी भी अन्य पार्टियों की तरह परिवारवाद की ओर अग्रसर होने लगी है। प्रारंभ में टीएमसी का बहुत बड़ा जनाधार बना था। टीएमसी ने बंगाल में 35 साल पुराने वामदलों के शासन को उखाड़ फेंका था। जनता को टीएमसी पर पूरा भरोसा था क्योंकि वह लोगों के हितों और कल्याण के लिए काम करती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। टीएमसी का जनाधार बिल्कुल खिसक गया है। बंगाली लोग क्रांति पसंद करते हैं। यहा क्रांति लोगों के हितों से जुड़ी होती है। उम्मीद है कि बंगाल में लोकतंत्र फिर से स्थापित होगा। चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह बंगाल में निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से राज्य में चुनाव करायेगा। चुनाव सही तरीके से हो गए तो निश्चित रूप से बंगाल में बड़े स्तर पर बदलाव होगा। बीजेपी के एजेण्डों पर उनका मानना है कि हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार गौ-तस्करी और निवेश जैसे बुनियादी एजेण्डों को शामिल करेंगे ताकि बंगाल विकसित प्रदेशों की श्रेणी में अग्रसर हो। इनका कहना है कि बंगाल में बीजेपी का जनाधार धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीती हैं। 4 सीटें को मामूली अंतर से हारे हैं। बीजेपी ने सभी माओवादी क्षेत्रों की लोकसभा सीटें जीती हैं। इनका मानना है कि बंगाल में बीजेपी 200 से अधिक सीटें जीतेंगी और वामदल 10-12 सीटों पर सिमट जाएंगे। मुकुल दा का मानना है कि टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने का जो सिलसिला चल रहा है वह आगे भी जारी रहेगा और कई नेता अभी भी बीजेपी में आएंगे। क्योंकि टीएमसी अब वह पार्टी नही रही जिसमें रहकर काम किया जाए। मुकुल दा का कहना है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान के विभाजन में भारत के बंगाल और पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। इसलिए नागरिकता कानून का लागू होना बहुत आवश्यक है। अब केन्द्र को निर्णय लेना है कि वह कब इस कानून को लागू करता है। लेकिन मेरा सुझाव है कि जल्दू लागू होना चाहिए। बंगाल के तमाम बार्डर क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए जमे हैं। टाटा के नैनो कार प्रोजेक्ट पर इनका कहना है कि उस समय मैं टीएमसी में था और यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने इसका विरोध किया था। टीएमसी ने टाटा के प्रोजेक्ट का लाभ नही उठाया। टाटा के प्रोजेक्ट के बाद बंगाल में कोई निवेश ही नही आया क्योंकि इसके बाद सभी निवेश डरने लगे और निवेश करने में कतराने लगे। माओवादी नेता छत्रधर मेहतो के विषय में मुकुल दा ने कहा कि मेहतो रेल पटरी पर बम रखने के आरोप में यूएपीए एक्ट में जेल गए थे। इस बम ब्लास्ट में 107 लोग मारे गए थे। आज ममता सरकार ने मेहतो को पैरोल पर छोड़ दिया है। यह गलत परंपरा है। मेहतो को जो पेरोल मिली है वह सुप्रीम कोर्ट से मिली है लेकिन पेरोल की रिपोर्ट तो ममता सरकार ने भेजी थी। टीएमसी के चुनाव मैनेजमेंट प्रमुख प्रशांत किशोर पर मुकुल दा का मानना है कि प्रशांत किशोर पार्टी के लिए नही हैं। प्रशांत बंगाल के विषय में क्या जानते हैं और वह क्या चुनावी रणनीति बना सकते हैं। बंगाल की रणनीति सिर्फ बंगाल का जमीनी नेता ही बना सकता है, जो बंगाल के विषय में जानता हो। बाहरी व्यक्ति रणनीति नही बना सकता। मेरा टीएमसी छोड़ने का मूल कारण टीएमसी के मूल सिद्धांतो से हटना है।

बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता पर ममता ने अपनायी आक्रामक शैली

बंगाल के पहाड़ी इलाकों में इसके प्रभाव के कारण भाजपा को इसका फायदा मिलता रहा है। 2009 में भाजपा के जसवंत सिंह को और 2014 में एसएस अहलुवालिया को लोकसभा पहुंचाने में जीजेएम की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। 2019 में भी भाजपा के राजू बिष्टो जीजेएम के सहयोग से लोकसभा पहुंचे। 2011 और 2016 के विधानसभा चुनावों में जीजेएम को तीन-तीन सीटें मिलीं। अब जीजेएम के एनडीए से अलग होने के बाद और टीएमसी को समर्थन की घोषणा से भाजपा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विमल गुरूंग ने भाजपा पर उनकी मांगों को नजरअंदाज करने और वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है। हालांकि टीएमसी ने अलग गोरखालैंड पर अपना रूख साफ करते हुए इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। अब जीजेएम की अगली रणनीति क्या होती है और यह पहाड़ी क्षेत्रों की राजनीति को कितना प्रभावित करती है यह देखना अहम होगा।

Scanned with CamScanner

बगैर सरकार की साजिश के मनीष शुक्ला की हत्या नही हो सकती थी - शीलभद्र दत्तो (एम.एल.ए., टी.एम.सी.)

बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्तोस भी मनीष शुक्ला की हत्या से आहत हैं। दत्तो का कहना है कि मनीष भले ही टीएमसी का नेता नही बीजेपी का नेता था लेकिन उसके जैसे इंसान की हत्या नही होनी चाहिए थी। वो सिर्फ नेता भर नही था। वह एक ईमानदार, कर्मठ, जनहितैषी समाजसेवी था। समाजसेवी का दुनिया से जाना सबके लिए दुख की बात है। क्योंकि राजनेता तो खूब बन जाते हैं लेकिन समाजसेवी कम ही बनते हैं। मनीष शुक्ला बैरकपुर में बहुत लोकप्रिय था। यहां की 80 प्रतिशत जनता उससे जुड़ी थी। वह क्षेत्र का उभरता चेहरा था। दत्तो का कहना है कि मेरे और मनीष के राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद भी बहुत अच्छे संबंध थे। वह मेरे छोटे भाई के तरह था। मनीष की हत्या क्यों हुई, मुझे अचंभित करती है। मनीष सामाजिक काम बहुत करता था। टीटागढ़ क्षेत्र मनीष की ताकत थी। क्योंकि वह यहां के गरीबों की बहुत मदद करता था। मनीष का सृष्टि एनजीओ बहुत काम करता था। सृष्टि के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैम्प में भी पढ़ना चाहता था, जैसे कई कार्यक्रम होते थे। शीलभद्र जी का मानना है कि मनीष की हत्या बगैर सरकार की साजिश के नही हो सकती। निश्चित रूप से इसकी हत्या की बड़ी साजिश रची गई थी। क्योंकि मनीष के कारण टीएमसी को भारी नुकसान उठाना पड़ता। इस साजिश में कौन शामिल है, मैं नही बता सकता। इससे पहले शहर में इतनी बड़ी राजनीतिक हत्या नही हुई है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दत्तो का कहना है कि इस बार टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। हालांकि यह भी सत्य है कि अभी बीजेपी में बंगाल में कोई बड़ा नेता नही है जो पब्लिक में पसंद हो। बीजेपी को मजबूत नेता खड़ा करना होगा, जो टीएमसी से टक्कर ले सके। उन्होंने टीएमसी के बारे में कहा कि मुकुल राय के बीजेपी में आने से टीएमसी कमजोर हुई है। इस समय टीएमसी की हालत खराब है। बीजेपी को भी मुकुल राय का उपयोग करना चाहिए। शीलभद्र दत्तो ने तृणमूल कांग्रेस की मौजुदा रणनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। इनका मानना है कि टीएमसी में जो कुछ भी हो रहा है वह पतन का रास्ता है। धीरे-धीरे कर बड़े-बड़े नेता टीएमसी छोड़ रहे हैं। पार्टी को खासकर ममता बैनर्जी को इस पर

टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्तो से बातचीत करती हुई जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक

पश्चिम बंगाल में फिर सिर उठा रहा है माओवाद

पश्चिम बंगाल के झारखंड से सटे इलाकों में नौ साल बाद एक बार फिर माओवाद सिर उठाने लगा है। हाल में इलाके में माओवादियों के कई पोस्टर नजर आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप है तो मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। इससे पहले बीते महीने भी माओवादियों ने लोगों से स्वाधीनता दिवस समारोहों के बहिष्कार की अपील की थी। कोई नौ साल से इलाके में माओवाद का कोई नामोनिशान नहीं था। उससे पहले माओवादी सक्रियता की वजह से इलाके के तीन जिलों, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया को जंगल महल कहा जाता रहा है। बाद में ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम मेदिनीपुर का हिस्सा रहे झाड़ग्राम को भी जिले का दर्जा दे दिया। दूसरी ओर, इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव भी तेज हो गया है। सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने बीजेपी का नाम लिए बिना इन पोस्टरों को

Scanned with CamScanner

विचार करना चाहिए। बावजूद उसके भी टीएमसी हाईकमान कुछ नहीं कर रहा है। माओवादी नेता छत्रधर मेहतो को छोड़ने के सरकार के फैसले को भी दत्तो ने गलत बताया है। राजनीतिक फायदे के लिए किसी अपराधी को छोड़ना गलत परंपरा है। आपको बता दें कि लेफ्ट सरकार के समय मेहतो ने ज्ञानेश्वरी ट्रेन की पटरी पर बम रखा था, जिसमें 107 लोगों की जानें गई थी। जबसे ही मेहतो जेल में बंद था। अभी हाल ही में ममता सरकार ने मेहतो को पैरोल पर छोड़ा है। जेल से छूटते ही टीएमसी ने मेहतो को स्टेट सेकेट्री बना दिया है और मेहतो की पत्नी को भी टीएमसी में बड़ा पद दिया है। बताया जाता है कि लालगढ़, मिदनीपुर, पुरूलिया, पश्चिम मदनीपुर, झारग्राम, विष्णुकपुर पर मेहतो की अच्छी पकड़ है। ममता सरकार ने इन क्षेत्रों में टीएमसी को लाभ पहुंचाने के लिए ही मेहतो को जेल से छुड़वाया है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में बीजेपी जीती है। यहां से सुभाष सरकार, सौमित्र खान, ज्योतिरमय मेहतो जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। टीएमसी इन क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने के लिए मेहतो का इस्तेमाल करना चाहती है। मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी को लेकर दत्तो का कहना है कि वर्तमान समय में बंगाल की सरकार में अभिषेक का इंटरफेयर ज्यादा हो गया है। ममता बैनर्जी पार्टी के महत्वपूर्ण पद अभिषेक को दे रही है, जिससे पार्टी को भी नुकसान हो रहा है और पार्टी के नेता भी नाखुश हैं। टीएमसी के कद्दावर और लोकप्रिय नेता हैं शिवेन्दु अधिकारी। ममता बैनर्जी के बाद शिवेन्दु नंबर दो की पॉजीशन रखते हैं। वह यूथ बिंग के लीडर हैं। शिवेन्दु तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब यह पद अभिषेक बैनर्जी को दे दिया है, जबकि शिवेन्द्र जनप्रिय और युवा वर्ग के विश्वसनीय नेता माने जाते हैं। मुर्शीदाबाद, जंगीपुर, बेहरामपुर माल्दा जिलों का आब्जर्बर शिवेन्द्रु अधिकारी को बनाया था तो सभी जगह से टीएमसी जीती थी। मतलब टीएमसी मजबूत होती गई। लेकिन जैसे ही इन जिलों से आब्जर्बर पद से हटा दिया गया तो वहां से कांग्रेस के अधिरंजन सिंह चुनाव जीते। मतलब टीएमसी कमजोर हुई और कांग्रेस मजबूत। वहीं बाकुंडा, पुरूलिया जिले के आब्जर्बर अभिषेक बेनर्जी थे। वहां टीएमसी चुनाव हारी थी। हारने के बाद इन जिलों में शिवेन्दु अधिकारी को भेजा। अब यहां से भी शिवेन्द्रु को हटा दिया गया। मतलब साफ है कि अभिषेक बैनर्जी को मजबूत करने के लिए ममता बैनर्जी ने यह सारी उठापटक की। परिणाम में क्या निकला टीएमसी कमजोर होती जा रही है। शीलभद्र दत्तो का मानना है कि इस तरह की पार्टी की रणनीति पार्टी के हित में नही है। हमारी लड़ाई ममता बेनर्जी से नहीं अभिषेक बेनर्जी को लेकर है। असंतुष्टों का जो दौर चल रहा है वह अभिषेक बेनर्जी को लेकर है। दत्तो आगे बताते हैं कि अभिषेक बैनर्जी के क्षेत्र में हिन्दुओं को वोटिंग ही नही करने दिया जाता है। मुसलमान हावी हैं और हिन्दुओं को परेशान किया जाता है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के सवाल पर उनका मानना है कि अभी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना ठीक नही है। वहीं शारदा चिटफंट मामले पर दत्तो का रुख कुछ अलग ही है। इनका मानना है कि इस मामले को बीजेपी अभी क्यों लायी। वहीं कोल माइंस पर दत्तो ने ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने कहा कि प्रदेश के वर्धमान और चिरगुम जिले कोल माइंस जिले हैं। यहां पर कोल का खुला खेल होता है। कोयले का अवैध कारोबार होता है। सरकार की बिल्कुल भी पकड़ नही है। इस अवैध कारोबार में बंगाल के नेता शामिल हैं। बड़े स्तर पर कार्यवाही की जाए तो बंगाल के बड़े-बड़े नेता फंसेंगे। नागरिकता कानून पर दत्तो का कहना है कि बंगाल में बड़े स्तर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। यही वह समय है जब नागरिकता कानून की पहल होनी चाहिए। वहीं गोरूपाचर (गाय तस्करी) को लेकर इन्होंने कहा कि प्रदेश में गोरूपाचर उच्च स्तर पर होता है और इस गोरखधंधे में बड़े-बड़े नेता शामिल हैं। राज्य से गायों को बांग्लादेश भेजा जाता है। यह करोड़ों का कारोबार है। राजनैतिज्ञ, पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं। सीबीआई जांच में सतीष कुमार (बीएसएफ कमाण्डर), मकबूल गिरफ्तार हो चुके हैं। ये टीएमसी के ही लोग हैं। इस मामले पर बीजेपी फायदा ले सकती है। बीजेपी को आंदोलन करना चाहिए। क्योंकि बंगाल का कोई इंसान गिरफ्तार नही हुआ। बंगाल में क्रांति को पसंद किया जाता है। यहां पर आंदोलनों को प्राथमिकता दी जाती है।

जहां एक साजिश बताया है वहीं बीजेपी का आरोप है अगले साल होने वाले चुनावों से पहले सियासी फायदे के लिए टीएमसी माओवाद को बढ़ावा दे रही है।

ताजा मामला पश्चिम बंगाल के झारखंड से लगे इलाकों में बीते नौ वर्षो से माओवाद का कोई नामलेवा नहीं रहा है। वर्ष 2011 में उनके नेता किशनजी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद इलाके में शांति बहाल हो गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के बाद इलाके के आदिवासियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए थोक के भाव विकास योजनाएं शुरू की थीं और उनका असर भी नजर आने लगा था। दो साल पहले भी एक बार इलाके में माओवादियों के सक्रिय होने की खबरें आई थीं। लेकिन पुलिस और इलाके में तैनात केंद्रीय बलों की चुस्ती की वजह से माओवादियों को दोबारा संगठित होने का मौका नहीं मिला।

लेकिन अब इलाके में माओवादियों की

Scanned with CamScanner

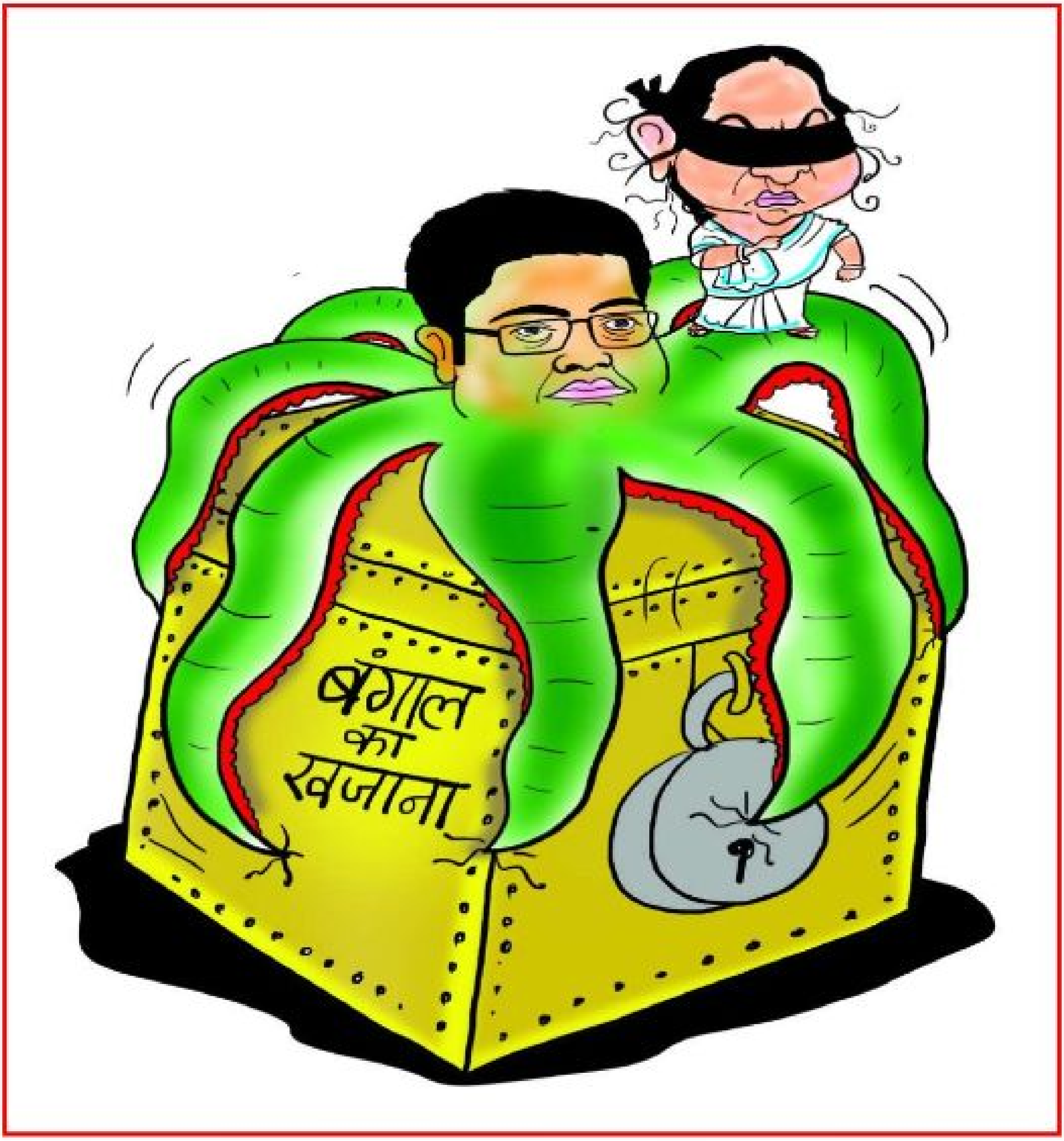

ओर से लिखे धमकी भरे पोस्टरों के सामने आने से इलाके में आतंक फैल गया है। पहले इलाके में तैनात केंद्रीय बलों की कई टुकड़ियां अब हटा ली गई हैं। पुलिस को संदेह है कि अगले साल होने वाले अहम चुनावों से पहले माओवादी एक बार फिर संगठित होने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना के दौर में लॉकडाउन के दौरान सरकार का पूरा ध्यान इस महामारी से निपटने में रहा है। इस वजह से शायद उन्होंने इलाके में पांव जमाने का प्रयास शुरू किया हो।

Scanned with CamScanner

औवेसी बिगाड़ेंगे टीएमसी का खेल

बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को गहरी सियासी चोट देने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम ऐलान कर चुके हैं कि अब अगली बारी पश्चिम बंगाल की है। बिहार चुनाव में सीमांचल में 5 सीटें झटककर ओवैसी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। और जब वह कह रहे हैं अब मौत भी उन्हें नहीं रोक सकती.. तो इस बयान को सियासी पंडित और अन्य सियासी दल भी गंभीरता से लेने लगे हैं। ओवैसी के ऐलान से अब यह सवाल उठने लगा है कि उनकी पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को कितनी चोट दे सकती है? सियासी पंडित साफ इशारा कर रहे हैं कि एआईएमआईएम के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने पर तृणमूल कांग्रेस की अल्पसंख्यकों पर पकड़ कमजोर हो सकती है। बंगाल में अगले साल (2021) में चुनाव होने हैं और वहां का राजनीतिक पारा गरमाने लगा है।

बंगाल में कितने मुस्लिम वोटर्स?- बंगाल में 2011 में वाम मोर्चे को हराने के बाद से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को ही अल्पसंख्यक मतों का फायदा मिला है। एआईएमआईएम के इस फैसले पर टीएमसी का कहना है कि ओवैसी का मुसलमानों पर प्रभाव हिंदी और उर्दू भाषी समुदायों तक सीमित है, जो राज्य में मुस्लिम मतदाताओं का सिर्फ छह प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल में 30 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं। अल्पसंख्यक, विशेषकर मुसलमान, 294 सदस्यीय विधानसभा में लगभग 100-110 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वैसे भी मुस्लिम वोटर्स चुनावी रण में प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ तृणमूल के लिए हमेशा फायदेमंद रहे है। इनमें से अधिकांश ने पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, जो भगवा दल के विरोध में हमेशा उनके लिए विश्वसनीय रहे हैं।

ओवैसी की पार्टी की यह तैयारी- वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं का कहना है कि एआईएमआईएम के यहां चुनाव लड़ने से समीकरण यकीनन बदल सकता है। मिशन पश्चिम बंगाल के लिए एआईएमआईएम ने राज्य में 23 जिलों में से 22 में अपनी यूनिट बनाई हैं।

ममता से पुरानी है तकरार- एआईएमआईएम ने पिछले साल नवंबर में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ रैली में ममता बनर्जी पर परोक्ष रूप से निशाना साधने के बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच जंग शुरू हो गई थी, जो अब चुनावी मैदान तक पहुंच गई है। असदुद्दीन ओवैसी की सफलता मुस्लिम मतदाता की सोच में बड़े बदलाव का संकेत इसलिए है कि पिछले बहत्तर सालों से मुसलमान मुस्लिम पार्टियों का साथ देने से बचते रहे हैं। लगता है कि अलग-अलग राज्यों में बीजेपी को हराने वाली पार्टियों की तलाश और उन पर दांव लगाते-लगाते मुसलमान थक गया है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद देश में मुस्लिम राजनीति एक बार फिर विमर्श के केंद्र में आ गई है। ममता का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला भविष्य की राजनीति के संकेत दे रहा है। बंगाल में मुसलमानों वोटों का बंटवारा ममता को कमजोर करेगा। ये हालात बीजेपी को फायदा दे सकते हैं। ओवैसी बंगाल में अगर थोड़ी सी भी ताकत इकट्ठा करेंगे तो ममता की राजनीति का आधार हिल सकता है।

वैसे, इलाके में माओवादी पोस्टर मिलने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 15 अगस्त को मिले पोस्टरों में लोगों से स्वाधीनता दिवस समारोहों के बायकाट की अपील की गई थी। उसके बाद कुछ लोगों ने जंगल में माओवादियों को देखने का भी दावा किया। ताजा पोस्टरों में इलाके में सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को धमकियां देते हुए काम बंद करने को कहा गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्य

Scanned with CamScanner

ममता सरकार द्वारा माओवादी नेता छत्रधर मेहतो को जेल से छुड़वाना कितना जायज?

हाल ही में ममता सरकार ने रेलपटरी पर बम रखने के आरोप में जेल में बंद माओवादी नेता छत्रधर मेहतो को जेल से छुड़वाया है। बताया जाता है कि आदिवासी जिलों झाड़ग्राम, पुरूलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी मेदिनीपुर में मेहतो की अच्छी पकड़ है। वहीं पिछले कुछ चुनावों में इन जिलों में बीजेपी ने अच्छी पकड़ बनाई है और माओवादियों का झुकाव बीजेपी की तरफ मुड़ा है। इसी झुकाव को टीएमसी की ओर करने के लिए ममता बैनर्जी ने पैरोल पर मेहतो को छुड़वाया है। ममता को लगता है कि मेहतो के कारण इन जिलों में टीएमसी मजबूत होगी। टीएमसी ने मेहतो को अपनी पार्टी में स्टेट सेक्रेटरी का पद भी दिया है। साथ ही मेहतो की पत्नि को भी पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के कदम उठाना कितना जायज है।

में माओवादियों के दोबारा संगठित होने का अंदेशा जताया था। उनका कहना था, कुछ नेताओं की मदद से राज्य में माओवाद एक बार फिर सिर उठाने का प्रयास कर रहा है।

कभी गढ़ था जंगल महल

झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल का जंगल महल इलाका किसी दौर में माओवादियों का गढ़ रहा है। खासकर लेफ्टफ्रंट सरकार के दौर में तो इलाके में किशनजी के नेतृत्व में इन माओवादियों की तूती बोलती थी और हत्या और अपहरण रोजमर्रा की घटना हो गई थी। इलाके के लालगढ़ में 2 नवंबर, 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के काफिले पर बारूदी सुरंग के जरिए जानलेवा हमला भी हुआ था। तब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी इलाके में एक फैक्टरी के शिलान्यास के सिलसिले में वहां थे। वर्ष 2009 से 2011 के दौरान तो इलाके में माओवाद चरम पर पहुंच गया था। इस दौरान छह सौ से ज्यादा आम लोग और 50 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी माओवादियों के हाथों मारे गए थे। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने 80 माओवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी मार गिराया था।

झारग्राम में माओवादी पोस्टर

वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद ही 24 नवंबर को इलाके के सबसे बड़े माओवादी नेता कोटेश्वर राव उर्फ किशन की एक पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद माओवादियों की कमर टूट गई थी। उसके बाद कई नेताओं ने हथियार डाल दिया था या फिर इलाका छोड़ कर चले गए थे। इलाके में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि 1990 के दशक के आखिरी दौर में भी इलाके में इसी तरह के राजनीतिक फेरबदल की वजह से माओवादियों को अपने पांव जमाने में सहायता मिली थी। वर्ष 2010-11 के दौरान तो किशन के नेतृत्व में माओवादियों ने झाड़ग्राम के अलावा पुरुलिया, बांकुड़ा व पश्चिमी मेदिनीपुर के ज्यादातर हिस्सों पर अपनी पकड़ बना ली थी। लेकिन किशन की

Scanned with CamScanner

ममता राज में घटती जा रही हिंदुओं की संख्या

पश्चिम बंगाल में 1951 की जनसंख्या के हिसाब से 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या में भारी कमी आयी है। 2011 की जनगणना ने खतरनाक जनसांख्यिकीय तथ्यों को उजागर किया है। जब अखिल स्तर पर भारत की हिन्दू आबादी 0.7 प्रतिशत कम हुई है तो वहीं सिर्फ बंगाल में ही हिन्दुओं की आबादी में 1.94 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि बहुत यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की आबादी में 0.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि सिर्फ बंगाल में मुसलमानों की आबादी 1.77 फीसदी की दर से बढ़ी है, जो राष्ट्रीय स्तर से भी कहीं दुगनी दर से बढ़ी है। दरअसल ममता राज में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके धार्मिक क्रियाकलापों पर रोक के पीछे तुष्टिकरण की नीति है। लेकिन इस नीति के कारण राज्य में अलार्मिंग परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। प. बंगाल के 38,000 गांवों में 8000 गांव अब इस स्थिति में हैं कि वहां एक भी हिन्दू नहीं रहता, या यूं कहना चाहिए कि उन्हें वहां से भगा दिया गया है। बंगाल के तीन जिले जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या बहुमत में हैं, वे जिले हैं मुर्शिदाबाद जहां 47 लाख मुस्लिम और 23 लाख हिन्दू, मालदा 20 लाख मुस्लिम और 19 लाख हिन्दू, और उत्तरी दिनाजपुर 15 लाख मुस्लिम और 14 लाख हिन्दू। दरअसल बंगलादेश से आए घुसपैठिए प. बंगाल के सीमावर्ती जिलों के मुसलमानों से हाथ मिलाकर गांवों से हिन्दुओं को भगा रहे हैं और हिन्दू डर के मारे अपना घर-बार छोड़कर शहरों में आकर बस रहे हैं।

मौत के बाद रातों-रात संगठन बिखर गया था। उस दौर में इलाके में पांच सौ से ज्यादा माओवादी सक्रिय थे।

राजनीतिक विवाद

अब ताजा मामले के बाद सत्तारुढ़ टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के बीच राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। दरअसल इसके पीछे टीएमसी का वह फैसला है जिसके तहत उसने पूर्व माओवादी छत्रधर महतो को पार्टी की एक समिति में शामिल किया है। छत्रधर महतो 10 साल बाद हाल में ही जेल से छूटे हैं। उनके खिलाफ वर्ष 2008 में बुद्धदेव के काफिले पर हमले का भी आरोप था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का आरोप है, तृणमूल कांग्रेस जंगल महल में अपने पैरों तले खिसकी जमीन दोबारा पाने के लिए माओवदियों के नाम पर आतंक फैला रही है।

ममता राज में बेरोजगारी, गरीबी और दहशतगर्दी चरम पर

माओवादी पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में दहशत की वजह बने हुए हैं खासकर जंगलमहल क्षेत्र में। इस पूरे इलाके में पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया, झारग्राम और बाँकुड़ा जैसे जिले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी) का गढ़ बने हुए हैं। साल 2009 से 2011 के बीच माओवादी जंगलमहल में एक अलग क्षेत्र बनाने में

पश्चिम बंगाल में गौ तस्करी बड़ा मुद्दा

पश्चिम बंगाल में गौ तस्करी की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं और ममता सरकार गौ तस्करी में शामिल लोगों को संरक्षण दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में गौ तस्करी के मामलों में काफी वृद्धि हुई है और इसका विरोध करने वालों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अगस्त में भारत-बांग्लादेश सीमा पर गौ तस्करी की घटना में संघर्ष के दौरान एक बीएसएफ इंस्पेक्टर की मौत हो गयी थी और एक जवान घायल हो गया था। गौ तस्करी में तृणमूल कांग्रेस के लोग सीधे तौर पर शामिल हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन राज्य सरकार का इसमें सहयोग नहीं मिलता। 2021 में विस चुनाव में बीजेपी इस मुददे को जोरशोर से उठाने वाली है। बताया जाता है कि गौ तस्करी बंगाल के सीमावर्ती जिलों में बहुत होता है। क्योंकि मवेशियों को सीधे बांग्लादेश भेज दिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि गौ तस्करी का यह गोरखधंधा अरबों रूपये का है और इस धंधे में टीएमसी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इतना ही नहीं, बीएसएफ के जवान जिन मवेशियों को जब्त करते हैं, उन्हें माकूल खाना तो नहीं मिलता। गौरतलब है कि मवेशी वध, विशेष रूप से गाय वध, भारत में एक विवादास्पद विषय है। मवेशियों को

काफी हद तक कामयाब रहे थे।

वामपंथ के चरमपंथी समूह और सुरक्षाबलों के बीच तब गोलीबारी का लंबा दौर चला था। इस घटना में कुल 350 आम नागरिकों ने अपनी जान गँवाई थी और 80 माओवादी नेताओं पर कार्रवाई हुई थी। इसे पश्चिम बंगाल के जंगली कॉरिडोर का सबसे भयानक और कठिन अभियान माना जाता है। इसमें लगभग 50 सुरक्षाबल शहीद भी हुए थे। मल्लौला कोटेश्वर राव उर्फ़ किशन की हत्या के बाद इस घरेलू आतंकवादी समूह का प्रभाव लगभग ख़त्म हो गया था। इसके बाद पूरे इलाके में माओवादी गतिविधियाँ काफी कम हो गई थी।

ममता के माओवाद प्रेम से खतरे में पड़ सकती है बंगाल की राजनीति

ख़बरों की मानें तो ऐसा माना जाता है कि माओवादी झारखंड के सिंहभुम जिले में अपना कैम्प लगाते हैं। पीछे कुछ महीनों से माओवादी झारग्राम में काफी सक्रिय रहे हैं। पिछले कुछ समय में झारग्राम में ऐसी 4 घटनाएँ हुई हैं, जिनके आधार पर माओवादियों की मौजूदगी और सक्रियता का डर फिर से बढ़ रहा है। ऐसी जानकारियों के आधार पर राज्य प्रशासन और खुफ़िया एजेंसियों ने हालात नियंत्रण में करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है।

हैरानी की बात यह है कि माओवादियों को प्रदेश सरकार से पुरा सहयोग भी मिल रहा है। ममता बनर्जी ने छत्रधर मेहतो को

Scanned with CamScanner

गौ-तस्करी के आरोप में सीबीआई ने बीएसएफ कमाण्डर सतीश कुमार को गिरफ्तार किया था।

इसको रोकने के लिये भारत के विभिन्न राज्यों में कानून भी बनाये गये हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों और अन्य दुश्मनों और मसौदे के मवेशियों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। 26 अक्टूबर 2005 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विरोधी गाय हत्या कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। भारत में 29 राज्यों में से 20 में वर्तमान में हत्या या बिक्री को प्रतिबंधित करने वाले विभिन्न नियम हैं। गायों का केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जहां गाय वध पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में मौजूदा मांस निर्यात नीति के अनुसार, गोमांस (गाय, बैल का मांस और बछड़ा) का निर्यात प्रतिबंधित है। मांस, शव, बफेलो के आधे शव में भी हड्डी निषिद्ध है और इसे निर्यात करने की अनुमति नहीं है। केवल भैंस के बेनालेस मांस, बकरी और भेड़ों और पक्षियों के मांस को निर्यात के लिए अनुमति है। 26 मई 2017 को बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने पूरे विश्व में पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाया है।

ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न हिस्सा और एक आवश्यक आर्थिक आवश्यकता के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। अहिंसा के नैतिक सिद्धांत और पूरे जीवन की एकता में विश्वास के कारण विभिन्न भारतीय धर्मों द्वारा मवेशी वध का भी विरोध किया गया है।

माओवादियों का बीजेपी की ओर झुकाव, सकते में ममता बैनर्जी

टीएमसी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति में शामिल किया था। महतो 10 साल तक जेल में रह चुका है और माओवादी संगठनों के लिए काम भी करता था।

राज्य से वाममोर्चा सरकार को हटाने में कभी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को माओवादियों के एक धड़े का खूब समर्थन मिला था। हालांकि बदले हालात में अब माओवादियों का झुकाव राज्य में भाजपा की ओर होता दिखायी देता है। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को हथियार बनाकर माओवादी अब खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुट गये हैं।

गौरतलब है कि सिंगूर और नंदीग्राम जमीन आंदोलन के वक्त माओवादियों के आला नेतृत्व का पूरा समर्थन तृणमूल कांग्रेस की ओर था। इस संबंध में माओवादी नेता किशनजी के बयान भी खूब आते थे। लालगढ़ आंदोलन के प्रमुख छत्रधर महतो का साथ भी तृणमूल को मिला था। हालांकि वर्ष 2011 में शीर्ष माओवादी नेता किशनजी की मौत के बाद बंगाल में एक तरह से माओवादियों का सफाया हो गया।

छत्रधर महतो को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट(यूएपीए) के तहत जेल में डाल दिया गया। माओवादियों का आला नेतृत्व ध्वस्त कर दिया गया था और उसके बाकी बचे कैडर इधर-उधर बिखर गये

Scanned with CamScanner

सीएए, एनआरसी का मुद्दा

2019 में बड़ा समर्थन मिलने के बाद बीजेपी को यह अहसास हो गया था कि थोड़ा सा जोर और लगाया जाए तो पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में झंडा फहरा सकती है। इसलिए बंगाल बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजंस (एनआरसी) को लेकर राज्य का माहौल गर्मा दिया। लेकिन बीजेपी का पाला वहां उन ममता बनर्जी से पड़ा है जिन्होंने कांग्रेस से निकलकर राज्य में अपना वजूद बनाया है। वो ममता बनर्जी जिन्होंने बरसों तक खूंटा गाड़कर बैठे रहे वाम दलों को वहां की सत्ता से सिर्फ़ अपने दम पर उखाड़ फेंका है। ममता बनर्जी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ जोरदार रैलियां की और सड़कों पर निकलकर यह दिखा दिया कि विपक्षी नेताओं में मोदी–शाह से मुकाबले का माद्दा सिर्फ उनके भीतर है। लेकिन कोरोना संकट के कारण माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया। इस बीच, प्रवासियों के लिए ट्रेनें चलाने से लेकर, लॉकडाउन लगाने और कई मुद्दों पर तृणमूल और बीजेपी आमने–सामने आते रहे। ममता को इस बात का अहसास है कि 2014 की उनकी 34 सीटें 2019 में घटकर 22 हो गई हैं। वह यह भी जानती हैं कि बीजेपी दिन–रात हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी है। इसलिए वह बेहद सतर्क हैं और सक्रिय भी है।

थे। लेकिन जानकारी के मुताबिक, माओवादी फिर एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना के मुताबिक, जुलाई महीने से माओवादी एक बार फिर एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं।

इसके लिए माओवादियों द्वारा परचे बांटे जा रहे हैं। दूसरी ओर, नेतृत्व के संकट और जमीनी स्तर पर कैडरों की कमी से निपटने के लिए भाकपा (माओवादी) अब शहरी और बुद्धिजीवी युवाओं के अलावा दलितों और आदिवासियों को संगठन में शामिल करने का प्रयास कर रही है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को माना था देश के लिए खतरा

बदलता राजनीतिक समीकरण

कभी तृणमूल कांग्रेस का साथ देने वाले माओवादियों का झुकाव अब राज्य में भाजपा की ओर हो रहा है। माना जा रहा है कि माओवादी इलाके में बन रहे नये राजनीतिक समीकरणों का फायदा उठाने की कोशिश में हैं। इसी वर्ष मई में हुए पंचायत चुनावों में इन इलाकों में भाजपा को काफी कामयाबी मिली

Scanned with CamScanner

ममता को लगा बड़ा झटका, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी और मंत्री पद से दिया इस्तीफा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के खास माने जाने वाले तृणमूल कांग्रेस के ताकतवर नेता शुभेंदु अधिकारी ने नाराजगी की खबरों के बीच टीएमसी और परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे टीएमसी से उनकी बगावत की अटकलों को मजबूती मिली है। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। शुभेंदु ने ऐसे समय पर हुगली रिवर ब्रिज कमीशन चेयरमैन पद और मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, जब उनके पाला बदलने को लेकर अटकलें लग रही हैं। ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले दिग्गज टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी करीब 30 से 40 सीटों पर अच्छा प्रभाव रखते हैं। राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि पूर्वी मिदनापुर जिले से आने वाले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में वह पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल शुभेंदु ने अपना सियासी पत्ता नहीं खोला है, मगर उन्होंने लगातार दो पदों से इस्तीफा देकर संकेत दे दिया था कि वह अब टीएमसी में टिकने वाले नहीं हैं। शुभेंदु अधिकारी की ममता बनर्जी से बगावत की तस्वीर उस वक्त सामने आई, जब ट्रांसपोर्ट मंत्री शुभेंदी ने पूर्व मिदनापुर के नंदीग्राम में एक रैली को संबोधित किया, जहां आज से 13 साल पहले पार्टी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। इसी की याद में हुए कार्यक्रम में नंदीग्राम में शुभेंदु ने सभा को संबोधित किया। इसी नंदीग्राम की घटना ने ममता बनर्जी को बंगाल की कुर्सी तक पहुंचाया था। उस रैली में शुभेंदु ने कहा था कि पत्रकार और राजनीतिक पर्यवेक्षक मेरे राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। वे मुझे उन बाधाओं के बारे में बात करते हुए सुनना चाहते हैं जो मैं झेल रहा हूं और जो रास्ता मैं लेने जा रहा हूं। मैं इस पवित्र मंच से अपने राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं करूंगा। दरअसल शुभेंदु बंगाल में काफी ताकतवर राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनका प्रभाव न सिर्फ उनके क्षेत्र पर है, बल्कि पूर्वी मिदनापुर के अलावा आस–पास के जिलों में भी उनका राजनीतिक दबदबा है। राजनीतिक पंडितों की मानें तो शुभेंदु अधिकारी ममता बैनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बंगाल में संगठनात्मक बदलाव किया है, उससे भी वह नाखुश हैं। साथ ही शुभेंदु अधिकारी चाहते हैं कि पार्टी कई जिलों की 65 विधानसभा सीटों पर उनकी पसंद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। आपको बता दें कि दो बार सांसद रह चुके शुभेंदु अधिकारी का परिवार राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत है। पूर्वी मिदनापुर को कभी वामपंथ का गढ़ माना जाता था मगर शुभेंदु ने अपनी रणनीतिक कौशल से बीते कुछ समय में इसे टीएमसी का किला बना दिया है। अगर वह टीएमसी से बाहर होते हैं तो ममता बनर्जी को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के भाई दिब्येंदु तमलुक से लोकसभा सदस्य हैं, जबकि तीन भाई–बहनों में सबसे छोटे सौमेंदु कांथीनगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उनके पिता सिसिर अधिकारी टीएमसी के सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य हैं, जो कांथी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंदीग्राम आंदोलन की लहर पर सवार होकर शुभेंदु 2019 में तमलुक सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद वह 2014 भी वह जीते। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद उन्हें ममता कैबिनेट में परिवहन मंत्री बनाया गया। बताया जाता है कि न सिर्फ पूर्वी मेदनीपुर जिला बल्कि मुर्शिदाबाद और मालदा में भी उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने और टीएमसी को मजबूत करने के लिए काम किया है। क्योंकि वह ग्रास रूट लेवल के नेता हैं, इसलिए बीते कुछ समय में उनकी स्वीकार्यता भी काफी बढ़ी है। उन्हें मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा और बीरभूम जिलों में टीएमसी के आधार का विस्तार करने का भी श्रेय दिया जाता है। इस तरह से राजनीतिक पंडितों का मानना है कि शुभेंदु अगर टीएमसी से अलग होते हैं तो इसका असर काफी सीटों पर दिख सकता है। यानी शुभेंदु बंगाल में ममता की करीब 30 से 40 सीटें खराब करने की क्षमता रखते हैं।

थी। उसके बाद इलाके में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच हिंसक संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इलाके में भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। जानकारों का मानना है कि झाड़ग्राम व पुरुलिया पर सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस की पकड़ धीरे-धीरे कमजोर हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, 90 के दशक के आखिरी दौर में भी आदिवासी बहुल इलाकों में इसी तरह के राजनीतिक फेरबदल की वजह से माओवादियों को अपने पांव जमाने में सहायता मिली थी। वर्ष 2010-11 के दौरान

Scanned with CamScanner

रोहिंग्या शरणार्थियों से देश को खतरा फिर भी सरकार बनाने के लिए ममता बनी उनकी हमदर्द

पश्चिम बंगाल की राजनीति हर दिन एक इबारत लिखती जा रही है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह से राजनीति का जो स्वरुप देखने को मिल रहा है वो समझ के परे है। कभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मार पीट करते हैं तो कभी उनकी रैली में आंसू गैस के गोले और लाठियां बरसाई जाती है। लेकिन हद हो गई जब ममता बैनर्जी के इशारे पर नाचने वाले समर्थकों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले को रोक कर उन पर पत्थर बाजी शुरु कर दी। निश्चित तौर पर इस पूरे घटना क्रम में ममता सर्मथकों का साथ रोहिंग्या प्रवासी भी दे रहे है। क्योंकि ममता सरकार इन दिनों इन रोहिंग्या प्रवासियों की हमदर्द बनी हुई है। हमदर्द बनना भी स्वभाविक है आखिर वोट बैंक का जो सवाल है। दरअसल टीएमसी खुद यह बहुत बेहतर ढंग से समझ चुकी है कि इस बार विधानसभा तक पहुंचने राह उनकी आसान नहीं है। पहले बीजेपी और फिर औवेसी की पार्टी का बंगाल में पदार्पण कहीं न कहीं उन्हें चुनाव हारने का भय महसूस करा रहा है। इसलिए अब टीएमसी पूरी तरह से रोहिंग्याओं के साथ मिलकर इस चुनाव को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा करके ममता कहीं न कहीं प्रदेश और देश की राष्ट्रीयता को तो खतरे में डाल ही रही है साथ ही आतंकवादियों को अपने घर में पनपने का मौका दे रही है। टीएमसी नेताओं को एक बात सीधेतौर पर समझ लेना चाहिए चुनाव काबिलियत और विश्वास से जीता जाता है न कि इस तरह से आतंकवादियों को घर में पालने से। खैर एक चिंता का विषय देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सबसे ज्यादा रोहिंग्याओं की संख्या पश्चिम बंगाल में ही है। इस बात को खुद बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने माना है उन्होंने अपने एक बयान में स्पष्ट किया है कि भारत में कुल दो करोड़ मुसलमान घुसपैठिए मौजूद हैं जिसमें से एक करोड़ पश्चिम बंगाल में ही हैं। यह आंकड़े सोचने पर मजबूर करते है क्योंकि इन्हीं लोगों से देश की अस्मिता को खतरा होता है। लेकिन ममता सरकार सबकुछ जानते समझते हुए भी नसमझ बनी हुई और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। पिछले दिनों रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर देश में उठ रहे सुरक्षा के सवालों पर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में 35 से ज्यादा संगठन करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की साजिश कर चुके हैं। इतना ही नहीं 35 से ज्यादा ऐसे संगठन हैं जो इन रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए देश भर से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। इस बात की जानकारी स्वयं ममता बैनर्जी सहित उनकी सरकार को भी है लेकिन फिर भी सत्ता में बने रहने के लिए ममता बैनर्जी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जबकि इन घुसपैठियों को न तो हिंदुस्तान से प्रेम होता है और ना ही इनके अंदर देशभक्ति का जोश। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ममता सरकार इन घुसपैठियों के साथ मिलकर अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो पाएगी और अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं राज्य और राष्ट्र को डुबो देने की शुरुआत ममता के इस एक कदम से ही होगी।

तो किशन के नेतृत्व में माओवादियों ने झाड़ग्राम के अलावा पुरुलिया, बांकुड़ा व पश्चिमी मेदिनीपुर के ज्यादातर हिस्सों पर अपनी पकड़ बना ली थी। किशन की मौत के बाद रातोंरात माओवादी संगठन बिखर गया था। उसके बाद राज्य समिति का वजूद ही खत्म हो गया था। बाकी सदस्यों ने या तो हथियार डाल दिये थे या फिर पकड़े गये थे।

कभी इन इलाकों में पांच सौ से ज्यादा

Scanned with CamScanner

बंगाल में अराजकता, असहिष्णुता चल रही है - जे.पी. नड्डा

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं द्वारा काफिले पर किए गए पथराव में बाल-बाल बचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, बंगाल में अराजकता चल रही है, असहिष्णुता चल रही है। मां दुर्गा के आशीर्वाद से जान बची है। टीएमसी समर्थक असामाजिक तत्वों ने मुझे मारने की अपनी एक भी कोशिश बाकी नहीं रखी थी। दरअसल 10 दिसम्बर को जेपी नड्डा जब डायमंड हार्बर के शिराकोल में जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे तब रास्ते में सत्तारूढ़ टीएमसी के लोगों ने उनके काफिले पर जमकर पथराव किया। इसमें न केवल नड्डा की गाड़ी चपेट में आई बल्कि कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल रॉय, शिव प्रकाश, संबित पात्रा समेत अन्य शीर्ष नेताओं की गाड़ियों पर भी पथराव किए गए। जैसे तैसे जेपी नड्डा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। जेपी नड्डा ने कहा, यह तय है कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार जाएगी और राज्य में कमल खिलेगा। यहां जंगलराज चल रहा है। मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका कारण है। कैलाश विजयवर्गीय और राहुल सिन्हा की गाड़ी की हालत देख लीजिए। बुरी तरह से टूट गई हैं। हम लोग बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे इसलिए बच गए। यहां गुंडाराज चल रहा है। बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी। इनकी मानसिकता विपक्ष को खत्म करने की है। इसलिए बंगाल के लोगों का आशीर्वाद मांगने यहां आया हूं। नड्डा ने कहा कि बंगाल के लोग संस्कृति और सभ्यता के लिए जाने जाते थे लेकिन ममता बनर्जी जो कर रही हैं उससे बंगाल का सम्मान गिरता जा रहा है। इसे सोनार बांग्ला बनाना ही होगा। रवींद्रनाथ टैगोर ने हमें अच्छी राह दिखाई थी। बंगाल सभ्यता की जननी है। जिस तरह से ममता शासन में इसका पतन हो रहा है, उसे सुधारना होगा।

अभिषेक संसद नहीं जाते- मुख्यमंत्री ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर हमला बोलते हुए नड्डा ने कहा कि यहां से जो सांसद हैं वह संसद में नजर नहीं आते। पुलिस का राजनीतिकरण कर चुके हैं। यह शर्मनाक है। बंगाल में कोई प्रशासन ही नहीं बचा है। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अगर केंद्रीय बलों की सुरक्षा ना मिले तो बंगाल में कोई घूम फिर नहीं सकता।

माओवादी सक्रिय थे। वर्ष 2008 से 2011 के बीच माओवादियों द्वारा लगभग सात सौ लोगों की हत्या किये जाने का आरोप है।

अर्बन नक्सल पर नजर

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, माओवादी संगठन फिलहाल नेतृत्व और कैडरों की कमी से जूझ रहा है। इसे पूरा करने के लिए माओवादी अब शहरी और बुद्धिजीवी युवाओं के अलावा दलितों और आदिवासियों को संगठन में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्बन नक्सल के मुद्दे पर तेज होती बहस के बीच संगठन के नेता बुद्धिजीवी युवाओं की तलाश में जुट गए हैं।

सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी

पश्चिम बंगाल के झारखंड से सटे इलाकों में नये सिरे से तेज होती माओवादी गतिविधियों ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। भूमिगत संगठन भाकपा (माओवादी) के पश्चिम बंगाल समिति के सचिव असीम मंडल उर्फ आकाश की अगुवाई में एक सशस्त्र गिरोह के विभिन्न

Scanned with CamScanner

बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के संभावित नाम

मुकुल रॉय | शिवेन्दु अधिकारी | सौरभ गांगुली | दिलीप घोष

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बगैर चुनाव मैदान में उतरने को ज्यादा फायदेमंद मान रहा है। पार्टी के ज्यादातर नेताओं का मानना है कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भाजपा को राज्य की 18 लोकसभा सीटें मिलीं, उससे उनके चेहरे पर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी करिश्माई प्रदर्शन कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि एक धड़ा संघ और भाजपा पृष्ठभूमि का है तो दूसरा धड़ा सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं का है। टीएमसी वाले धड़े के प्रमुख चेहरे पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय हैं और टीएमसी से बीजेपी में आ जाते हैं तो शिवेन्दु अधिकारी हैं। वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा की ओर से क्रिकेटर सौरभ गांगुली और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, एक केंद्रीय मंत्री सहित तीन से चार प्रमुख चेहरे दावेदार नजर आ रहे हैं। बीजेपी बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिये किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेगी। बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि अभी के लिये यह तय किया गया है कि हम किसी को भी अपने मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री

इलाकों में देखे जाने के बाद खतरे की घंटी बजने लगी है।

इसी साल जून और जुलाई में झारखंड में सुरक्षा बल के सात जवानों की हत्या के बाद वहां माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज होने के बाद इस गिरोह के बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में शरण लेने का अंदेशा है।

झाड़ग्राम में माओवादियों के दोबारा संगठित होने की खबरें भी मिल रही हैं। पहले राज्य के चार जिले माओवाद-प्रभावित जिलों की सूची में थे, लेकिन केंद्र की ओर से जारी ताजा सूची में सिर्फ झाड़ग्राम का ही नाम है।

क्या बंगाल में टीएमसी को पछाड़ भगवा झंडा बुलंद करने में कामयाबी दिला पाएंगे कैलाशजी

पश्चिम बंगाल में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां मंच से लेकर गली मोहल्ले तक भाषण के माध्यम से एक दूसरे पर तीखा प्रहार कर रही है। वहीं, दूसरी ओर इन राजनैतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ता सड़कों पर एक दूसरे का स्वागत पत्थर, लाठी, डंडे और लात-घूसों से कर रहे हैं। परिणाम चाहे जो लेकिन एक तो तय है कि बंगाल का राजनीतिक समीकरण बहुत जल्दी बदलने जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है बंगाल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आईएमआईएम की आमद है। बेशक यह पार्टी विधानसभा चुनाव में जितनी भी सीटें जीते लेकिन वोटों का समीकरण कहीं न कहीं इस पार्टी के आने से बिगड़ने वाला है। इस बात से बंगाल के दोनों प्रमुख पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नेता अच्छी तरह से परिचित है। यही वजह है कि भाजपा ने एक बार फिर बीजेपी महासचिव कैलाश

Scanned with CamScanner

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने 2016 का विधानसभा चुनाव भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर बिना कोई चेहरा सामने रखे ही लड़ा था। बीते चार वर्षों में हालांकि हावड़ा पुल के नीचे से काफी पानी बह चुका है और बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के लिये भाजपा प्रमुख चुनौती के तौर पर उभरी है। उसने परंपरागत विरोधी दलों माकपा और कांग्रेस को तीसरे और चौथे स्थानों पर पहुंचा दिया है। बीजेपी ने पिछले साल बंगाल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीतकर राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया था। उसे राज्य में 41 फीसद मत मिले थे और उसकी सीटें सत्ताधारी टीएमसी से सिर्फ चार कम थीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 सीटें मिलने के बाद ये किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी 2019 के चुनाव में 18 सीटें जीत जाएगी। इसके पीछे बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की जबरदस्त मेहनत और उनकी चुनावी रणनीति भी है। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय ने भी वहां लगातार दौरे करके माहौल बनाए रखा।

मुकुल रॉय- मुकुल रॉय भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। मुकुल रॉय पर बीजेपी हाईकमान का भरोसा भी दिखता है लेकिन उनके साथ माइनस प्वाइंट यह है कि वे तृणमूल से बीजेपी में आए हैं। ऐसे में पार्टी में पहले से काम कर रहे नेता उनके नाम पर राजी नहीं होंगे। उनके समर्थकों को मनाने के लिए पार्टी रॉय को राज्यसभा भेजने के बाद मोदी कैबिनेट के जल्द होने वाले विस्तार में केंद्रीय मंत्री बना सकती है। उनके समर्थक भी अपने नेता को बंगाल का मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं।

शिवेन्दु अधिकारी- जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी के कद्दावर नेता शिवेन्दु अधिकारी बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमुख नाम इनका ही होगा। क्योंकि बंगाल में अधिकारी का बड़ा नाम है।

सौरभ गांगुली- महान क्रिटर सौरभ गांगुली बंगाल में बहुत लोकप्रिय हैं। हालांकि अभी तक सौरभ ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वह बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी भी आश्वस्त है कि सौरभ बीजेपी में शामिल होंगे। यदि ऐसा होता है तो सौरभ भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि सौरी टीएमसी के डर के कारण बीजेपी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल ममता सरकार ने बंगाल के न्यू टाउन में आईसीएसई बोर्ड वाले 12वीं क्लास तक के स्कूल के निर्माण के लिए गांगुली को 2 एकड़ जमीन दी थी। लेकिन गांगुली के बीजेपी के तरफ झुकाव को लेकर ममता ने यह जमीन वापिस ले ली। बताया जाता है कि सौरभ से यह जमीन ममता सरकार ने कानूनी अड़चन का बहाना बनाकर वापिस ली है। जबकि हकीकत यह है कि सौरभ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।

दिलीप घोष- अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले घोष को उनके समर्थक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि 2019 में बीजेपी को मिली जीत का सेहरा घोष के सिर ही बांधा जाना चाहिए। लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे दिलीप घोष संघ के लिए कई राज्यों में काम कर चुके हैं।

विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कैलाशजी ने पार्टी को वहां पिछले चुनाव से बेहतर सीटें उपलब्ध करवाने में कोई कोर-कसर छोड़ेंगे। लेकिन यह बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का सिंहासन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। टीएमसी नेताओं द्वारा विजयवर्गीय की क्षमता को कम आंकना एक बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि जिन्होंने वर्ष 2014 में हरियाणा में उस समय बहुमत वाली सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की

टीएमसी नेताओं द्वारा विजयवर्गीय की क्षमता को कम आंकना एक बड़ी गलती हो सकती है

थी जिस समय वहां भाजपा ने सीएम पद का उम्मीदवार चुनाव के दौरान घोषित नहीं किया था। कैलाश विजयवर्गीय की इस कामयाबी को देखते हुए भाजपा ने उन्हें केंद्र में महासचिव की जिम्मेदारी देने का फैसला किया था। कुल मिलाकर बंगाल में भाजपा का झंडा बुलंद करने की प्रमुख जिम्मेदारी अब विजयवर्गीय पर है। औवेसी की पार्टी के आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और पार्टी यहां दो तिहाई बहुमत से सफलता अर्जित कर सरकार बनाएगी। कैलाश विजयवर्गीय का यह उत्साह क्या

Scanned with CamScanner

बंगाल में पहली मर्तबा भगवा झंडा बुलंद करने में कामयाब हो पाएंगे यह बड़ा सवाल है। जिसका जवाब आने वाले कुछ महीनों में स्वतः मालूम हो जाएगा। जानकारी के अनुसार एआईएमआईएम के यहां चुनाव लड़ने से समीकरण यकीनन बदल सकता है। मिशन पश्चिम बंगाल के लिए एआईएमआईएम ने राय में 23 जिलों में से 22 में अपनी यूनिट बनाई हैं। वहीं, देखा जाए तो एआईएमआईएम और टीएमसी के बीच पिछले साल नवंबर में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ रैली में ममता बनर्जी पर परोक्ष रूप से निशाना साधने के बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच जंग शुरू हो गई थी, जो अब चुनावी मैदान तक पहुंच गई है। हालांकि टीएमसी की ओर से देखा जाए तो ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी

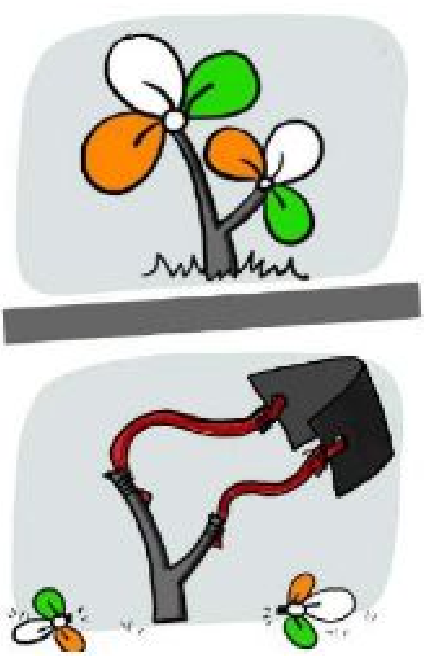

टीएमसी के लिए कमजोर कड़ी दिखाई जान पड़ते है। क्योंकि अभिषेक के व्यवहार से स्थानीय लोग बहुत संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ते और उन पर पहले से ही भ्रष्टाचार और दंगे उकसाने जैसे कड़े आरोप लगे हुए है जिससे कहीं न कहीं पार्टी की छवि धूमिल होती दिखाई जान पड़ती है।

हाथ से सरकती सत्ता से बौखलाई ममता का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हथियार बंद हमला

वर्ष 2021 की शुरूआती छह महीने पश्चिम बंगाल में ममता बैनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत अहम साबित होने वाला है। जितना अहम यह ममता के लिए होगा उससे कहीं ज्यादा अहम यह भाजपा के लिए भी होगा। क्योंकि यहां 292 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे

ममता बनाना चाहती हैं बंगाल को दूसरा बांग्लादेश

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानाशाही बढ़ती ही जा रही है। हाल के वर्षों में ममता बनर्जी ने अपनी तानाशाही में मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिससे लगता है कि वे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने पर तुली हुई हैं। ममता बनर्जी की वोट बैंक की राजनीति के कारण बंगाल के कई इलाके मुस्लिम बहुल हो चुके हैं और हिंदुओं का इन इलाकों में जीना भी दूभर हो गया है। राज्य में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या एक करोड़ से भी यादा हो चुकी है। अवैध घुसपैठ ने राज्य की जनसंख्या का समीकरण बदल दिया है। उन्हें सियासत के चक्कर में देश में वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसी सुविधाएं मुहैया करवा दी जाती हैं और इसी आधार पर वे देश की आबादी से जुड़ जाते हैं। बांग्लादेश के रास्ते पहले इन्हें पश्चिम बंगाल में प्रवेश दिलाया जाता है। फिर उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवा जम्मू से केरल तक पहुंचा दिया जाता है। बांग्लादेशी मुस्लिमों को 1971 से एक योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत, बंगाल, बिहार और दूसरे प्रांतों में बसाकर इस्लामिस्तान बनाने की तैयारी चल रही है। फरवरी, 2018 में सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने भी सीमापार से घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा, हमारे पश्चिमी पड़ोसी के चलते योजनाबद्ध तरीके से प्रवासन चल रहा है। वे हमेशा कोशिश और यह सुनिश्चित करेंगे कि परोक्ष युद्ध के जरिये इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया जाए। जानकारों का कहना है कि भारत का एक और विभाजन होगा और वह भी तलवार के दम पर। इन्होंने आशंका व्यक्त की है कि कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल में अब गृहयुद्ध होगा और अलग देश की मांग की जाएगी। बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम होगा और मुगलिस्तान की मांग की जाएगी। इन्होंने यह भी दावा किया है

Scanned with CamScanner

है। एक ओर जहां ममता बैनर्जी अपनी सरकार बचाए रखने के लिए साम,दाम,दंड, भेद अपना रही है। वहीं बिहार में सरकार बनाने के बाद भाजपा पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार को उखाड़ फेंकने के मकसद से बंगाल में आमद दे चुकी है। भाजपा नेताओं की इस हुंकार से बौखलाए टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच काफी झड़प चल रही है। सत्ता के मद में खोने को आतुर यह कार्यकर्ता एक दूसरे की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे। कुछ दिन पहले बंगाल के बर्धमान जिले के आसनसोल स्थित जामग्राम में रैली के दौरान बम भी फेंके गए। बंगाल में हुई एक हिंसक झड़प में भाजपा के सात कार्यकर्ता घायल हो गए। चुनावी मैदान में इस तरह की घटनाएं

बंगाल में उद्योगों की बहुत बुरी स्थिति है। पिछले 10 साल में बंगाल के कई उद्योग, फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं। ममता सरकार ने इन उद्योगों की ओर ध्यान ही नहीं दिया है।

कि यह सब ममता बनर्जी की सहमति से होगा। 2013 में पहली बार बंगाल के कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने अलग मुगलिस्तान की मांग शुरू की। इसी साल बंगाल में हुए दंगों में सैकड़ों हिंदुओं के घर और दुकानें लूट लिए गए और कई मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। इन दंगों में सरकार द्वारा पुलिस को आदेश दिये गए कि वो दंगाइयों के खिलाफ कुछ ना करें। जानकारों ने बंगाल में बिगड़ते जनसांख्यिकीय संतुलन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने हिंदुओं की घटती और मुस्लिमों की तेजी से बढ़ती आबादी का जि करते हुए देश के एक और विभाजन की तस्वीर प्रस्तुत की है। उन्होंने तथ्य के साथ दावा किया है कि स्वतंत्रता के समय पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की आबादी 30 प्रतिशत थी, लेकिन यह घटकर अब महज 8 प्रतिशत हो गई है। जबकि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। इतना ही नहीं कई जिलों में तो यह आबादी 63 प्रतिशत तक है। उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिम संगठित होकर रहते हैं और 27 फीसदी आबादी होते ही इस्लामिक शरिया कानून की मांग करते हुए अलग देश बनाने तक की मांग करने लगते हैं। इन्होंने दावा किया है कि इस्लामिक देश बनाने की सूत्रधार ममता बनर्जी बनने जा रही हैं। इन्होंने अपने दावे में तथ्य भी दिए हैं और कहा है कि यह सब अरब देशों की फंडिंग से होने जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि ममता सरकार ने सऊदी अरब से फंड पाने वाले 10 हजार से यादा मदरसों को मान्यता देकर वहां की डिग्री को सरकारी नौकरी के काबिल बना दिया है। सऊदी से पैसा आता है और उन मदरसों में वहाबी कट्टरता की शिक्षा दी जाती है। पूरे बंगाल

में मुस्लिम मेडिकल, टेक्निकल और नर्सिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। इनमें मुस्लिम छात्रों को सस्ती शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा कई ऐसे अस्पताल बन रहे हैं, जिनमें सिर्फ मुसलमानों का इलाज होगा। मुसलमान नौजवानों को मुफ्त साइकिल से लेकर लैपटॉप तक बांटने की स्कीमें चल रही हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि लैपटॉप केवल मुस्लिम लड़कों को ही मिले, मुस्लिम लड़कियों को नहीं। हिंदुओं को भगाने के लिए जिन जिलों में मुसलमानों की संख्या यादा है, वहां के मुसलमान हिंदू कारोबारियों का बायकॉट करते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में मुसलमान हिंदुओं

Scanned with CamScanner

कोलकोता शहर की सड़कों पर लगी इन सफेद लाईट लगाने में अभिषेक बैनर्जी ने अरबों का भ्रष्टाचार किया है। जानकारों का कहना है कि इन लाईट्स को लगाने की जरूरत ही नहीं थी।

कोई नई नहीं है, लेकिन सत्ता के मद में चूर ममता सरकार के कार्यकर्ता किसी की जान लेने को पीछे हटते नहीं दिखाई देते। ममता सरकार की अराजकता का प्रमाण तब दिखाई दिया जब सिलीगुड़ी में भाजपा नेताओं द्वारा उत्तरकन्या घेराव सचिवालय का घेराव किया जा रहा था तभी ममता ने प्रशासकीय हथकंडों को अपनाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, तेजस्वी सूर्या, नितिश प्रमाणिक, डॉ. सुकांता सहित अन्य नेताओं पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छुड़वाए और ममता के गुंडे ने बम चलाए। इस दौरान कई भाजपा नेता बुरी तरह से घायल भी हुए।

ममता बैनर्जी की यह बौखलाहट जायज भी है। इतने सालों से सत्ता पर जमी बैठी

की दूकानों से सामान तक नहीं खरीदते। यही वजह है कि वहां से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन होना शुरू हो चुका है। कश्मीरी पंडितों की ही तरह यहां भी हिंदुओं को अपने घरों और कारोबार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ रहा है। ये वे जिले हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। बंगाल में बेहद गरीबी में जी रहे लाखों हिंदू परिवारों को कई सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं दिया जाता।

हिंदुओं का हो रहा है धर्म परिवर्तन- मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ ही आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और अपराध के मामले बढ़ने लगते हैं। आबादी बढ़ने के साथ ऐसी जगहों पर पहले अलग शरिया कानून की मांग की जाती है और फिर आखिर में ये अलग देश की मांग तक पहुंच जाती है। इस समस्या के लिए इस्लाम को ही जिम्मेदार है। 2007 में कोलकाता में बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ दंगे भड़क उठे थे। ये पहली कोशिश थी जिसमें बंगाल में मुस्लिम संगठनों ने इस्लामी ईशनिंदा (ब्लेसफेमी) कानून की मांग शुरू कर दी थी। 1993 में तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और उनको जबरन मुसलमान बनाने के मुद्दे पर किताब लज्जा लिखी थी। किताब लिखने के बाद उन्हें कट्टरपंथियों के डर से बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। वो कोलकाता में ये सोच कर बस गयी थी कि वहां वो सुरक्षित रहेंगी क्योंकि भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वहां विचारों को रखने की स्वतंत्रता भी है। मगर हैरानी की बात है कि धर्म निरपेक्ष देश भारत में भी मुस्लिमों ने तस्लीमा नसरीन को नफरत की नजर से देखा। भारत में उनका गला काटने तक के फतवे जारी किए

गए। देश के अलग-अलग शहरों में कई बार उन पर हमले भी हुए।

आतंक समर्थकों को संसद भेज रही ममता- ममता ने अब बाकायदा आतंकवाद समर्थकों को संसद में भेजना तक शुरू कर दिया है। जून 2014 में ममता बनर्जी ने अहमद हसन इमरान नाम के एक कुख्यात जिहादी को अपनी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा। हसन इमरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का सह-संस्थापक रहा है। हसन इमरान पर आरोप है कि उसने शारदा चिटफंड घोटाले का पैसा बांग्लादेश के जिहादी संगठन जमात-ए-इस्लामी तक पहुंचाया, ताकि वो बांग्लादेश में दंगे भड़का सके। हसन इमरान के खिलाफ एनआईए और सीबीआई की जांच भी चल रही है। दरअसल लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (एलआईयू) की रिपोर्ट के मुताबिक कई दंगों और आतंकवादियों को शरण देने में हसन का हाथ रहा है। उसके पाकिस्तानी

Scanned with CamScanner

ममता को अब यह एहसास हो गया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की राह इतनी आसान नहीं है जितना वो समझती है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में जहां तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और भाजपा को 10.16 फीसदी वोट के साथ सिर्फ 3 सीटें ही मिली थीं। वहीं, 2019 आते-आते परिस्थितियां बदल गई और लोकसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीएमसी की बौखलाहट को धुंआ देने का काम किया है एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने। हाल ही में ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कूदने का एलान कर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ओवैसी

कलकत्ता के सारे डिवाईडर्स, पार्को की बाउंड्री वाल यानि सारे शासकीय जगहों को नीली और सफेद पट्टी में पोता गया है। यह रंग टीएमसी का रंग है। इसलिए ममता सरकार ने ऐसा किया है। इस तरह की पुताई कई तरह के सवाल खड़े करती हैं।

खुफिया एजेंसी आईएसआई से रिश्ते होने के आरोप लगते रहे हैं। बंगाल का भारत से विभाजन करने की मांग अब जल्द ही उठने लगेगी। खतरा सिर्फ बंगाल पर नहीं है। देश के कई प्रदेशों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। इनकी आबादी अब तीन करोड़ के आसपास है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश में तीन करोड़ की अतिरिक्त आबादी उस देश के संसाधनों पर कितना बोझ बढ़ा सकती है। बहरहाल हम बिहार के चार जिलों की बात करते हैं। जहां के चार जिलों में इन घुसपैठियों के कारण आबादी का समीकरण बिल्कुल ही बदल गया है। किशनगंज में मुस्लिम सबसे अधिक है। इस जिले की कुल जनसंख्या 16.90 लाख है, जिनमें मुस्लिम 11.49 लाख और हिंदू 5.31 लाख हैं। कटिहार की कुल जनसंख्या 30.71 लाख है, जिसमें मुसलमानों की आबादी 13.65 लाख है। पूर्णिया की जनसंख्या 32.84 लाख है, जिसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी 12.55 लाख है। अररिया की कुल जनसंख्या 28.11 लाख है, जिसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी 12.07 लाख है।

मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ममता बैनर्जी कई मौकों पर दिखा चुकी हैं कि वह कुछ भी कर सकती हैं- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर हिंदुओं की आस्थाओं पर आघात करने से भी नहीं हिचकती हैं। मुस्लिम वोट के लिए ममता बैनर्जी हिंदू देवी-देवताओं को बांटने में भी पीछे नहीं रहती। हिंदुओं को बांटने के लिए ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं, राम की पूजा क्यों करें? झारगाम की एक सभा में ममता ने कहा

था कि बीजेपी राम मंदिर बनाने की बात करती है, वे राम की नहीं रावण की पूजा करती है। लेकिन हमारे पास हमारी अपनी देवी दुर्गा है। हम मां काली और गणपति की पूजा करते हैं। हम राम की पूजा नहीं करते।

हिंदुओं के हर पर्व के साथ भेदभाव करती हैं ममता बैनर्जी- ममता बैनर्जी ने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया है। कई ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने अपना मुस्लिम प्रेम जाहिर किया है और हिंदुओं के साथ भेदभाव किया है। सितंबर, 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से ममता बैनर्जी का हिंदुओं से नफरत जाहिर होता है। कोर्ट ने तब कहा था, आप दो समुदायों के बीच दरार पैदा क्यों कर रहे हैं। दुर्गा पूजन और मुहर्रम को लेकर राज्य में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। उन्हें साथ रहने दीजिए। हिंदू धर्म में दशहरे पर शस्त्र पूजा की परंपरा रही है। लेकिन मुस्लिम प्रेम में ममता बैनर्जी हिंदुओं की धार्मिक आजादी छीनने की हर

Scanned with CamScanner

यह सिंदूर की वही जमीन है जो वाम सरकार में टाटा समूह को नैनो कार प्रोजेक्ट के लिए दी थी। बाद में ममता सरकार के आते ही यह जमीन वापिस ले ली गई। आज यह सैकड़ों एकड़ जमीन बेकार ही पड़ी है।

की पार्टी के आने से टीएमसी का अल्पसंख्यक वोट कटेगा। देखा जाए तो देशभर में कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 30 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा संभव है। हालांकि ममता बनर्जी ने ओवैसी को खुली चुनौती देते हुए दावा किया है कि ओवैसी का असर सिर्फ हिंदी और उर्दू भाषी मुस्लिमों पर है, बंगाल के मुस्लिमों को लुभाना उनके बस की बात नहीं।

देखा जाए तो ममता के पश्चिम बंगाल में नई पारी शुरु करने में उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी की कार्यशैली और लोगों पर उनके द्वारा किया गया अत्याचार और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप रास्ते का रोड़ा बन

कोशिश करती रही हैं। सितंबर 2017 में ममता सरकार ने आदेश दिया कि दशहरा के दिन पश्चिम बंगाल में किसी को भी हथियार के साथ जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। हालांकि कोर्ट के दखल के बाद ममता बैनर्जी की इस कोशिश पर भी पानी फिर गया। 11 अप्रैल 2017 को पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के सिवड़ी में हनुमान जयंती के जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ममता सरकार से हिन्दू जागरण मंच को हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम इस आयोजन की अनुमति को लेकर बार-बार पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। धार्मिक आस्था के कारण निकाले गए जुलूस पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया। इसमें कई लोग घायल हो गए। जुलूस में शामिल होने पर पुलिस ने 12 हिन्दुओं को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आर्म्स एक्ट समेत कई गैर जमानती धाराएं लगा दीं। 10 अक्टूबर, 2016 को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश से ये बात साबित होती है। ममता बनर्जी ने हिंदुओं को अपने ही देश में बेगाने करने के लिए ठान रखी है। बीरभूम जिले का कांगलापहाड़ी गांव ममता बैनर्जी के दमन का भुक्तभोगी है। गांव में 300 घर हिंदुओं के हैं और 25 परिवार मुसलमानों के हैं, लेकिन इस गांव में चार साल से दुर्गा पूजा पर पाबंदी है। मुसलमान परिवारों ने जिला प्रशासन से लिखित में शिकायत की कि गांव में दुर्गा पूजा होने से उनकी

भावनाओं को ठेस पहुंचती है, क्योंकि दुर्गा पूजा में बुतपरस्ती होती है। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा पर बैन लगा दिया। एक तरफ बंगाल के पुस्तकालयों में नबी दिवस और ईद मनाना अनिवार्य किया गया तो एक सरकारी स्कूल में कई दशकों से चली आ रही सरस्वती पूजा ही बैन कर दी गई। ये मामला हावड़ा के एक सरकारी स्कूल का है, जहां पिछले 65 साल से सरस्वती पूजा मनायी जा रही थी, लेकिन मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता सरकार ने इसी साल फरवरी में रोक लगा दी। जब स्कूल के छात्रों ने सरस्वती पूजा मनाने को लेकर प्रदर्शन किया, तो मासूम बच्चों पर डंडे बरसाए गए। इसमें कई बच्चे घायल हो गए थे।

Scanned with CamScanner

पश्चिम बंगाल में कोयला का भारी अवैध कारोबार होता है, जिससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान होता है। सूत्रों का कहना है कि इस अवैध कारोबार में टीएमसी के नेता शामिल हैं।

सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण लालू प्रसाद यादव को काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। खैर यह तो आने वाला समय बताएगा कि ममता अपने सिरमौर को बचाने में कामयाब होती है या फिर भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी जीत का झंडा लहराती है।

अराजकरता में डूबा पश्चिम बंगाल मारने-मरने पर उतारू ममता सरकार

अगले साल पश्चिम बंगाल में आम चुनाव होने वाले हैं। चुनावों के नजदीक आते ही प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी अपने तानाशाही रवैये की ओर बढ़ने लगी हैं। अपने शासन का पूरा इस्तेमाल कर पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बना दिया है। विपक्षी

बंगाल का जूट उद्योग सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। यहां जूट से बने सामान सारे देश सहित विदेशों में भी निर्यात किए जाते थे लेकिन वर्तमान में जूट उद्योग धराशायी हो गया है। सरकार की अनदेखी के चलते ऐसा हुआ है।

Scanned with CamScanner

यह मृतक बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं के नाम की लिस्ट है, जिन्हें टीएमसी के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। हिंसा और हत्या के बीच इन सैकड़ों मृतकों के परिजनों पर दुःख का पहाड़ टूट गया है।

LIST OF SAHID OF BHARATIYA JANATA PARTY WEST BENGAL (ZONE-KOLKATA)

SL. no	Date of Death	Address	District	Name of the Sahid	Mondal Name	Family Person Name	Ph. No.	Relation
1	11/09/2017	Baruipur	SOUTH 24 PGS EAST	Soumitra Ghoshal	Baruipur Purba 1	Biswanath Ghosal	9083913406	Brother
2	19/12/2018	Kanpur, South 24 Paraganas	SOUTH 24 PGS EAST	Bubai Ghorai	Mograhat Zp 55	Mousumi Ghorai	7679633123	Wife
3	18/9/2017	Vill-Mahisamari, Po-Barabari, Ps- Gangasagar Costal	SOUTH 24 PGS WEST	Nirmal Mondal	Gangasagar	Ganga Mondal	8167736664	Wife
4	16/12/2016	Kultoli Gopalganj, MadhusudanPur	SOUTH 24 PGS WEST	Sushanta Halder	kultali 1	Anjana Halder	8509631851	Relative
5	26/07/2017	Budge Budge	SOUTH 24 PGS WEST	Prahlad Biswas	Budge Budge 1 (moukhali grama)	Rintu Biswas	9088720857	Brother
6	9/4/2018	Pathorpratima, Lakhhilantapur	SOUTH 24 PGS WEST	Susanta Pradhan				
7	27/07/2018	Dhanurhat anchal,Police station-Mandirbazar	SOUTH 24 PGS WEST	Saktipada Sardar	Mandir Bazar Zp36	Sujata Sarder	8167774268	Wife
8	18/08/2019	Jumai Naskar Haat, Kaligni River, Tolahaat P.S, Kakdwip	SOUTH 24 PGS WEST	Kader Molla	Kakdwip zp21	Tufan Molla	9734154554	Son
9	31/06/2019	Ramtanu Nagar , Laskar Para , Kakdwip, South 24 Pgs	SOUTH 24 PGS WEST	Sirajul Sekh	Madhusudanpur Kakdwip	Hasen Ali Sha	9735437658	Daughter husband
10	3/7/2020	Gangasagar	Diamond Harboir	Devashish Mandal				
11	4/6/2020	Kundakhali Godabar, Kultali Vidhansabha	South 24 Parganas	Late Shakuntala Haldar & her husband Late Bhim Halder	Kultali 4			
12	7/30/2020	Booth 132, Ghormara Gram Panchayat-2, Sagar Vidhansabha, Mathurapur	South 24 Parganas	Gautam Patra	Sagar Mandal 1			

पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर हमले, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस द्वारा प्रताड़ित करना आम हो गया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बेनर्जी सरकार में इस समय कुछ भी ठीक नही चल रहा है। पूरे राज्य में अराजकता और दहशत का माहौल व्याप्त है। फिर चाहे वह राजनेता हो या आम आदमी। सभी भय के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो प्रदेश में एक दम से तानाशाही शासन का आगाज हो गया है। दिनदहाड़े हत्या, अपहरण जैसी वारदातें आम बात हो गई हैं। इससे पहले भी बंगाल में अन्य पार्टियों की सरकारें हुई लेकिन आज तक बंगाल में ऐसी अराजकता नही फैली। 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे ही बीजेपी ने यहां अपना परचम लहराना प्रारंभ किया ममता सरकार बदले की भावना से काम करने लगी। क्या नेता और क्या आमजन। सबके प्रति तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हात्री होने लगे। प्रदेश की जनता ने वामदलों के 25 वर्ष के शासन को नकारते हुए राज्य में ममता बैनर्जी के हाथों में सत्ता सौंपी थी। लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि ममता सरकार के आने से प्रदेश में अमन चैन की लहर दौड़ेगी। प्रारंभ में ऐसा हुआ भी। लेकिन पिछले कुछ सालों से राज्य का माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। ममता सरकार ने नक्सलियों के आतंक को भी पीछे छोड़ दिया है।

एनसीआरबी के आंकड़ों अनुसार, वर्ष 2016 में बंगाल में राजनीतिक कारणों से झड़पों की 91 घटनाएं हुई और 205 लोग हिंसा के शिकार हुए। इससे पहले यानी वर्ष 2015 में राजनीतिक झड़प की कुल 131 घटनाएं दर्ज की गई थीं और 184 लोग इसके शिकार हुए थे। वर्ष 2013 में बंगाल में राजनीतिक कारणों से 26 लोगों की हत्या हुई थी, जो किसी भी राज्य से अधिक थी। हाल ही में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ था। यह हमला उस वक्त हुआ जब वह पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से जब गुजर रहे थे। उस दौरान कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके। पत्थर लगने से उनकी गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। बीजेपी ने इस हमले के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएमएम)

Scanned with CamScanner

LIST OF SAHID OF BHARATIYA JANATA PARTY WEST BENGAL (ZONE-UTTAR BANGA)

SL.no	Date of Death	Address	District	Name of the Sahid	Mondal Name	Family Person Name	Ph. No.	Relation
1	14/05/2018	Chowrongi, Gopalpur, Block-II, Booth No. 121	COOCH BEHAR	Dulal Bhowmick	ZP 12	Dipak Bhoumik	6360380414	Father
2	18/06/2019	Maruganj Kathal Bari, Natabari	COOCH BEHAR	Amanda Pal	ZP 28	Prasanta Pal	9733163873	Brother In law
3	22/04/2018	Balurghat	DAKSHIN DINAJPUR	Gopal Guin	Balurghat ZP-10	Tapoti Guin	7047676742	Wife
4	06/05/2018	Vill- Dugdugi,P.O -Kordoho, P.S- Tapan	DAKSHIN DINAJPUR	Uttam Burman	Tapan ZP-13	Alpona Burman	7872589357 /	Wife
5	14/05/2018	Hikandarpur, Katabari, Maligaon, Khusmundi Assembly, ZP:3, Booth no.37/157	DAKSHIN DINAJPUR	Bishu Tudu				
6	23/2/2018	Vill+ Po- Bang Kandi, Ps-Maynaguri,	JALPAIGURI	Khirod Roy (V)	Maynaguri			
7	16/06/2013	Jajol, Habibpur	MALDA	Nripen Mandal	Habibpur -Zp4	Malik Mondal	9932184711	Elder Brother
8	10-10-2016	Baishanb Nagar	MALDA	Ram Mandal	Kaliyachak 3-Zp37		9933810864	
9	29/03/2019	Daulatnagar, Harishchandpur	MALDA	Patanu Mondal	Harishchandrapur -Zp14	Utpal Mondal	8436641690	Brother
10	09/07/2019	Englishbazar Assembly, Hiracolony, Bhatkapara	MALDA	Asit Singh	English Bazar Gramin	Joyanto Singha	8617852481	Father
11	18/07/2017	Chopra	UTTAR DINAJPUR	Aren Singh	CHOPRA 3	Sukuntala Singha	9647091339 / 9733352849	Wife
12	04/08/2017	Vill- Raria, Po- Taherpur, Ps - raiganj Bamangram	UTTAR DINAJPUR	Toton Das	23 Raiganj	Nayan Das	7679888455	Brother
13	06-07-2018	Chilada, Dhaniya Basti Chopra	UTTAR DINAJPUR	Amirul Islam	Chopra 1	M.D Mahirul	9933447776	Brother
14	20/09/2018	Darivit, Islampur, Raiganj, Uttar Dianjpur	UTTAR DINAJPUR	Rajesh Sarkar	6 NO. Islampur	Jharna Sarkar	6296508966	Son
15	20/09/2018	Darivit, Islampur, Raiganj, Uttar Dianjpur	UTTAR DINAJPUR	Tapas Barman	6 NO. Islampur	Doly Barman	8617506646	Sister
16	7/13/2020	Bindal, Hematabad, Uttar Dinajpur	UTTAR DINAJPUR	MLA Debendra Nath Ray				
17	9/14/2020	Kukurkachuya,P.O-Bhulki P.S-Sahebganj	Coochbehar	Late Sambaru Barman	Mandal(ZP-25)	1.Achini Barman 2.Burdhi Barman	9883327120	1.Mother 2.Father

के विमल गुरुंग गुट पर शक जताया है। इससे पहले 2019 में भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ था। ऐसे ही एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता का मामला सामने आया था। इस महिला ने आरोप लगाया था कि ममता सरकार में उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। निगरानी की जा रही है। महिला ने परेशान होकर राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली में अर्जी तक लगाई है और अंदेशा जताया है कि उनकी ममता सरकार हत्या तक कर सकती है। वहीं भाजपा नेता मनीष शुक्ला की मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने 24 परगना जिले के बैरकपुर उप संभाग में

टीएमसी के मूल सिद्धांतो से भटकी ममता की अग्नि परीक्षा

टीटागढ़ के निकट गोली मारकर हत्या कर दी थी। भाजपा नेता की हत्या को लेकर राज्यपाल ने आरोप लगाया था, आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों को पश्चिम बंगाल पुलिस और मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से त्याग दिया है। इस नृशंस कार्य का तरीका आतंक सहित सभी एंगल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बता रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हुए इस हमले से पार्टी के नेताओं में रोष है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा नेताओं पर हमला किया जा रहा है। 2014 से अब तक 115 भाजपा कायकर्ता बंगाल में राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए हैं, जिसमें पुलिस द्वारा कोई प्रमाणिक कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन को भी सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्ती हो रहा है। वहीं मार्क्सवादी और वाम दलों के नेता भी खौंफजदा हैं। वह भी प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं और ममता सरकार को सत्ता से बाहर करने में बीजेपी के साथ खड़ी है।

Scanned with CamScanner

LIST OF SAHID OF BHARATIYA JANATA PARTY WEST BENGAL (ZONE-RARH BANGA)								
SL .no	Date of Death	Address	District	A	Mondal Name	Family Person Name	Ph. No.	Relation
1	4/4/2018	RANIBANDH,Vill-Puushya,po-Kadmadari,PS-Ranibandh	BANKURA	Ajit Murmu	Ranibandh-2	Brother In Law	7427938631/ 7718727983	
2	11-06-2018	LaxmiSagar Anchal, Bankathi Booth, Simlapal P.S	BANKURA	Ajit Ghosh	Simlapal-2			
3	10-09-2014	Domonpur	BIRBHUM	Sk.Enamul				
4	27/10/2014	Magra	BIRBHUM	Sk. Koushik	Ilambazar B			
5	06-07-2014	Kanur	BIRBHUM	Sk. Rahim	Ilambajar A			
6	17/10/2016	Malbarpur	BIRBHUM	Indrajit Dutta	Mayureswar-1			
7	21/10/2018	Danrka Village, Labhpur P.S, Birbhum	BIRBHUM	Tapas Bagdi	Labpur -A			
8	23/04/2018	Siuri	BIRBHUM	Sheikh Dildar	Suri Block-1			
9	04-06-2018	Bautia, Nalhati	BIRBHUM	Lalu Das	Nalhati-1		7639800345	
10	14/5/2019	Dubrajpur, Ranjan Bazar,Ward no-1	BIRBHUM	Suresh Oram	Dubrajpur	Golai Oram	6295624155	Yonger Brother
11	9/9/2018	Vill Ramkrishnapur, Ps- Nanur	BIRBHUM	Swarup Garai	Nanur	Anup Gorai	7001509343	Elder Brother
12	17/08/2019	Mirbandh Village, Po-Darka	BIRBHUM	Hillal Sheikh(Dalu)	labpur -A		7478421038	
13	31/5/2019	Joypur, Birampur	BISHNUPUR	Tonmoy Santra	Joypur-1	Bikash Santra	9800564055	Brother
14	21/7/2019	Berugram,	BISHNUPUR	Gopal Chandra pal		Sanjoy Pal	8016121876	Son
15	19/09/2017	Monteshwar	BURDWAN	Baneshwar Roy	Zp-16(Monteswar)		9144801264	
16	9/10/2018	Kaksha, Asansol	BURDWAN	Saudip Ghosh	ZP-4 (Durgapur			
17	30/3/2019	vidhansabha, Village- Pandu, Loksabha- Bolpur, Kete gram	KATWA	Shushil Mondal	Zp-46	Avijit Mondal	8317503726	Son
18	2/6/2018	Vill- Dava, Balarampur	PURULIA	Dulal Kumar	ZP-30 (Balarampur)	Kisan Kumar	8617854255	Brother
19	11-06-2018	Amtard, Balarampur	PURULIA	Jagannath Tudu				
20	27/08/2018	Jaypur, Purulia	PURULIA	Damodar Mandal	ZP-16(Joypur)		9002487216	
21	27/9/2018	Jaypur, Purulia	PURULIA	Niranjan Gope	ZP-16 (joypur)			Wife
22	18/04/2019	Vill-sonabona	PURULIA	Sishupal Sashis	Zp-8(arsa)		7029847455	
23	29/5/2018	Village- Supurdih, Balarampur Mandal	PURULIA	Trilochon Mahato	Zp-11	Vivek Mahato	8709733943	Elder Brother
24	6/10/2019	Village- Saprolehana, Bolpur Gramin, Nanoor Vidhansabha, Birbhum	BIRBHUM	Animesh Chakraborty	Bolpur Gramin			
25	10/21/2019	Booth 241, Nanoor Vidhansabha	BIRBHUM	Shankari Bagdi				
26	9/7/2020	Kalna, Purba Bardhaman	KATWA	Late Rabin Paul	Kalna(ZP-28)	Bhaskar Hazra	9064750494	Son in Law

सत्ताधारी पार्टी का हस्तक्षेप भी राजनीतिक हिंसा का एक बड़ा कारण है। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि **रूल ऑफ लॉठ** को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है और कानूनी व पुलिसिया मामलों में भी राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। यही वजह है कि पुलिस अफसर निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। बंगाल में राजनीतिक झड़पों में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य तौर पर तीन वजहें मानी जा रही हैं- बेरोजगारी, विधि-शासन पर सत्ताधारी दल का वर्चस्व और भाजपा का उभार।

दिनदहाड़े लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की हत्या ममता बनर्जी सरकार द्वारा की जा रही है। बंगाल में सरकार के संरक्षण में जिस तरह की उद्दंडता, अराजकता और खून-खराबा हो रहा है वो निश्चित तौर से किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम को शर्मसार करता है। अचंभे की बात है कि लोकतंत्र और जनतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देने वाली ब्रिगेड अब बंगाल के मामले पर खामोश है। पिछले कुछ महिनों में ममता बनर्जी की सरकार में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ क्रूरता और राजनीतिक हिंसा में वृद्धि हुई है। बंगाल उसके प्रशासन के तहत जल रहा है, जो हिंसक तत्त्वों का संरक्षण करता है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि अब बंगाल की जनता को तय करना है कि परिवारवाद चाहिए या विकासवाद। बीजेपी बंगाल को विकास की राह पर ले जाना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी अपने भतीजे को अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने प्रशासन का राजनीतिकरण किया है, राजनीति का अपराधीकरण किया है। बंगाल में तीन कानून हैं, अपने भतीजे के लिए, वोट बैंक के लिए, लोगों के लिए। बंगाल एकमात्र राय है जहां अभी भी सांप्रदायिक हिंसा जारी हैं। मुर्शिदाबाद में एक परिवार के सभी तीन सदस्यों, जिनमें आठ-वर्षीय बच्चा और उसकी गर्भवती मां भी शामिल हैं, को धारदार

Scanned with CamScanner

LIST OF SAHID OF BHARATIYA JANATA PARTY WEST BENGAL (ZONE-NABADWIP)

Sl.no	Date of Death	Address	District	Name of the Sahid	Mondal Name	Family Person Name	Ph. No.	Relation
1	06-07-2014	Bamangachi	BARASAT	Sourav Choudhury	Barasat Gramin	Saraj Chodhury	9748174377/ 7003837089	Father
2	20/06/2019	Bhatpara	BARRCAKPORE	Nazmul Karim	Amdanga		9062897871	
3	6/20/2019	H/ No-23 BLNO-7, Kachari Road, Po-Kankinara, Ps- Jagaddal	BARRCAKPORE	Lala Chowdhury	Bhatpara	Birju Chowdhury	8145970890	Father
4	20/05/2019	Bhatpara	BARRCAKPORE	Dharambir Shaw	Bhatpara			
5	20/05/2019	Bhatpara	BARRCAKPORE	Rambabu Shaw	Bhatpara-2			
6	20/05/2019	ward number 7, Kanchrapara, Ps- Jagaddal Assembly- Bhatpara	BARRCAKPORE	Chandan Shaw	Jagatdal 2	Rajesh Shaw	8981396070/ 9123071059	Relative
7	06-05-2017	Tatra Bank Of India , Paikpara, Po- Bhebia, Ps- Basirhat	BASIRHAT	Kartik Ghosh	Basirhat II	Brobhas Ghosh	8637229781	Son
8	08-06-2019	Sandeshkhali Assembly - Hatgachi Anchal - PS - Nazat	BASIRHAT	Pradip Mondal	Sandeshkhali - I Uttar	Puja Mondal	8926735870/ 8642812868	Wife
9	08-06-2019	Sandeshkhali Assembly - Hatgachi Anchal - PS - Nazat	BASIRHAT	Sukanta Mondal	Sandeshkhali - I Uttar	Sukumar Mondal	7063127190	Brother
10	08-06-2019	Bhangipara, Hatgachia, Ps- Nazat	BASIRHAT	Debdas Mondal	Hatgachia			
11	13/6/2019	Basirhat Uttar, Takipur Anchal	BASIRHAT	Smt. Swaraswati Das	Hasnabad	Santanu Mondal	7797768036	Relative
12	02-07-2019	Vill- Tablanga, Beginagar	MURSHIDABAAD	Dharma Hazra	ZP 56	Sannasi Hazra	8158588960/ 9074738851	Uncle
13	14/05/2019	Kumarpur, Beldanga P.s, ZP- 61	MURSHIDABAAD	Tapan kumar Mandal	ZP 61	Now all family involved in TMC	9732793843	
14	24-06-2019	Vill- Milermath, Santipur, Haripur, Sangsad -4,	NADIA DAKSHIN	Biplab Shikadar	ZP 28	Sufal Shikdar	7384846075	Son
15	24/05/2019	Loksabha - Ranaghat chakdah , 2 no Radhakrishna colony , ward no - 19	NADIA DAKSHIN	Santu Ghosh	Chakdah Town	Moni Karmakar	8642023483/ 9635521046	Sister
16	19/05/2018	Tangra, Block-Chapra, P.S. - Bhimpur, Assembly- Chapra,	NADIA UTTAR	Jaydev Pranti	ZP 20	Sanatan Pranti	8670880478	Brother
17	06-07-2019	Fakirtala, swarupganj, Nadia Uttar	NADIA UTTAR	krishna Debnath	ZP 28	Prinka Debnath	7063280179	Relative
18	17/05/2019	Loksabha - Krishnagar , Assembly - chapra booth no - 187	NADIA UTTAR	Haradhan Mridha	ZP 30	Saradip Mridha	8637387680	Son
19	6/19/2019	Sutiya, Hridaypur Anchal, Chapra Block 18 ZP, Nadiya	NADIA	Ahmad Sheikh	ZP 18			
20	18/10/2019	Shantipur, Nadia	Nadiya	Supriya Banerjee				
21	12/10/2019	Booth No. 25 of Habibpur Village Panchayat under ZP No. 12 in Ranaghat block.	Ranaghat	Harlal Debnath	ZP 33			
22	12/24/2019	Booth 112, Charjajira Village, ZP 44, Kalyani Vidhansabha	NADIA	Mangal Chowdhury	18			
23	7/14/2020	Poragacha Panchayat, ZP-21 Mandal, Krishnanagar Uttar Vidhansabha	NADIA	Bapi Ghosh	ZP 21			
24	6/10/2020	Titagarh	Barrackpore	Manish Shukla				

हथियारों से काट डाला गया। बताया जाता है कि इस परिवार का मुखिया आरएसएस का कार्यकर्ता था। मतलब साफ है कि ममता शासन में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा जा रहा है। यदि यही लोकतंत्र की परिभाषा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं।

हमले और हत्या की इस राजनीति को बंगालवासी कभी भूल नहीं सकते।

बीजेपी से खौफजदा हैं ममता बैनर्जी

2019 के लोकसभा चुनाव में ममता के गढ़ में भाजपा ने सेंध लगाई। लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल तीसरा सबसे बड़ा सूबा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। वह 42 में से 18 सीटों पर विजयी रही। पिछली बार उसे 02 सीटें मिली थीं। वहीं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 34 सीटें मिली थीं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता परिवर्तन की पूरी उम्मीद लगाए बैठी है। बीजेपी की यह उम्मीद सच्चा ई में भी बदल सकती है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षो से प्रदेश में अच्छी पकड़ बनाए हुए है। जमीनी स्तर पर बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है। जगह-जगह बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि इस बार के विस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में भी

Scanned with CamScanner

LIST OF SAHID OF BHARATIYA JANATA PARTY WEST BENGAL (ZONE-MEDNIPUR)

S.no	Date of Death	Address	District	Name of the Sahid	Mondal Name	Family Person	Ph. No.	Relation
1	27/6/2018	Booth 159, Kota Village, Nukunda Anchal, Goughat Vidhansabha, Aarambagh Loksabha	ARAMBAGH	Kashinath Ghosh	ZP - 47	Munmun Ghosh	6296720259	Wife
2	22/6/2019	16 no Booth Baugali Tala, Ghatal Purba Mandal	GHATAL	Ajoy Maudi	Ghatal Purba Mandal	Biswajit Jana	6297701519	Friend
3	21/08/2017	Uluberia	HOWRAH GRAMIN	Arun Pramanik	Uluberia Uttar 4 no.		8981848963	
4	06-09-2019	Udaynarayanpur Assembly, Amta P.S. Chanulia village	HOWRAH GRAMIN	Somotul Doloi	Udaynarayanpur - 5		9002308967	
5	04-05-2016	Jhargram	JHARGRAM	Sujit Bera				
6	16/09/2017	Beliabera Mondal, Bhol Gram	JHARGRAM	Mastal Digar	Belebara		7059218511	
7	2/11/2018	Vill- Dhamal, Po. Gopiballavpur-2 , Choucita 1	JHARGRAM	Rampada Bera	Gopiballavpur - 2	Rasbihari Bera	7384791334	Son
8	11/5/2018	Vill - junsola , Gopiballav pur 2 no block,booth no 176	JHARGRAM	Ramen singh	Belebara	Amlan Singh	6294850035	Cuison
9	21/05/2016	Ramnagar	KANTHI	Sk. Azhar	Ramnagar Block - 1 Purba		7384331732	
10	3/12/2017	Katapal, Daton	MEDINIPUR PASCHIM	Bipin Das	Dantan - 1 Uttar	Subal Das	6297282780 / 7551001790	Son
11	04-09-2018	Goaltore	MEDINIPUR PASCHIM	Bahadur Murmu	Gowaltor Dachin		8670348847 /	
12	12/10/2017	Chandrakona- 1, Khirpai -4, Ghatal	MEDINIPUR PASCHIM	Sujit Ray	Ramjibon Pur	Pinaki Roy	9679833492	Son
13	13/5/2018	Keshyari Uttar Mandal	MEDINIPUR PASCHIM	Monu Hansda	Kshiyari	Amlan Singh	8001953335	Cousin
14	15/5/2018	Daspur, Bolck-I, Tatalpur Village, Sarberia Anchal	MEDINIPUR PASCHIM	Sukdev Maity	Daspur - 1 Paschim Mandal	Sumita Maity	9547367577 /	Wife
15	2/8/2019	Medinupur West	MEDINIPUR PASCHIM	Raja Majumdar	Medinipur Town Purba	Anupama Bose	6294424287 / 9932066027	Sister
16	10/27/2019	Aarmbagh Paur Mandal Ward 8, Booth number 108	Arambagh	Late Aamir Ali Khan				
17	2/24/2020	Jorhat, Sankrail	HOWRAH Sadar	Shekhar Mallik	Jorhat			
19	7/28/2020	41, Arjuni Booth, Haldia 2 Mandal	Paschim Medinipore	Purnachanda Das				
20	15.08.2020	Doulatchak Village, Natipur-2, Khanakul,	ARAMBAGH	Sudarshan Pramanik				
21	13.08.2020	Booth 178, Goghat	AARAMBAGH	Ganesh Roy				
22	8/21/2020	Barida GP, Booth no. 7, Egra B.I	Kanthi	Sk Liyakat	Egra 1 Uttar	Sk Hakim.	9733441515	Son
23	9/19/2020	Purba Medinipur, Mayna, Bakcha Anchal 8,	TAMLUK	Dipak Mondal				

होने वाला है। वैसे प्रदेश में वामदल भी अपना वर्चस्वै बनाए हुए हैं। अभी बीजेपी के सुशासन और टीएमसी के कुशासन के बीच मुकाबला होने वाला है। गौरतलब है कि बीजेपी की बंगाल में मजबूती कोई चमत्कार नही है। बीजेपी ने बंगाल में अपनी जमीन तलाशने की शुरूआत 2014 के पहले ही कर दी थी। एक रणनीति के तहत बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल का प्रभारी बनाकर भेजा। जिम्मेदारी सौंपी कि राज्य में बीजेपी को खड़ा करना है। विजयवर्गीय ने भी अपनी कुशलता और कर्मठता से कम समय में बंगाल में बीजेपी को खड़ा कर दिया। जिसको हम 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से समझ सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में करीब 30 फीसदी मुसलमान और 24 फीसदी दलित हैं। दोनों ही समुदायों में टीएमसी का जनाधार काफी घटा है।

पश्चिम बंगाल में करीब 30 फीसदी मुसलमान और 24 फीसदी दलित हैं। दोनों ही समुदायों में टीएमसी का जनाधार काफी घटा है। ममता बैनर्जी को गलतफहमी है कि मुस्लिम वोट टीएमसी के साथ खड़ा है लेकिन यह सच्चाई नही है। टीएमसी में मुस्लिमों का रूझान घटा है। वामदल के प्रति मुस्लिमों का रूझान बढ़ा है। अब बीजेपी के लिए जरूरी है कि वह वामदलों को साथ लेकर ममता के विरूद्ध लड़ाई लड़े तो निश्चित रूप से बीजेपी और वामदलों को लाभ होगा। यदि आवश्य क हो तो बीजेपी बंगाल में गठबंधन बनाकर भी चुनाव मैदान में उत्तर सकती है। वैसे इस बार भाजपा को

Scanned with CamScanner

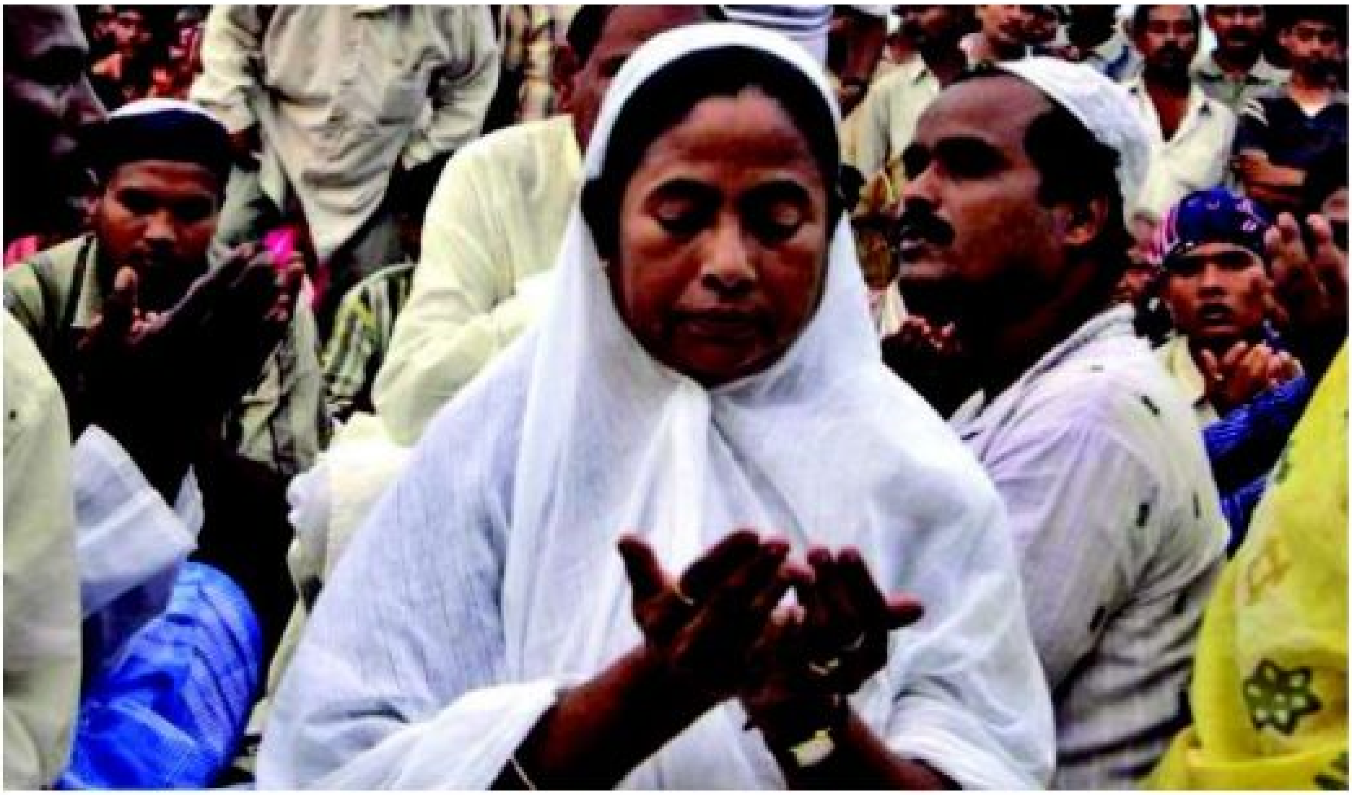

पश्चिम बंगाल से बड़ी सफलता की उम्मीद है। वहीं, ममता भी अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो टीएमसी के लिए यह चुनाव बड़ा मुश्किल होने वाला है। प्रदेश की जनता में ममता की जो छवि बनी थी वह धुंधली होती जा रही है।

हम जानते हैं कि बंगाल में उद्योग-धंधे कम हैं। जिससे रोजगार के अवसर नहीं बन रहे हैं। जबकि जनसंख्या बढ़ रही है। खेती से बहुत फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे में बेरोजगार युवक कमाई के लिए राजनीतिक पार्टी से जुड़ रहे हैं ताकि पंचायत व नगरपालिका स्तर पर होने वाले विकास कार्यों का ठेका मिल सके। स्थानीय स्तर पर होने वाली वसूली भी उनके लिए कमाई का जरिया है। वे चाहते हैं कि उनके करीबी उम्मीदवार किसी भी कीमत पर जीत जाएं। इसके लिए अगर हिंसक रास्ता अपनाना पड़े, तो अपनाते हैं। असल में यह उनके लिए आर्थिक लड़ाई है। इसका कारण भी स्पष्ट है कि ममता सरकार प्रारंभ से ही उद्योगों के प्रति गंभीर नहीं है। यहां तक कि वह टाटा नैनो के प्रोजेक्ट को भी अपने प्रदेश में नहीं बचा पायी। उस समय यह मामला काफी उछला था। मीडिया रपट बताती हैं कि तृणमूल की हिंसा का जवाब विपक्षी पार्टियां खासकर भाजपा भी दे रही है। खासतौर से उत्तर बंगाल में तृणमूल के लिए भाजपा चुनौती बनकर उभरी है। बंगाल में अब मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। दूसरी ओर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य में वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद भाजपा ने बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण तेज कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस भाजपा का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट अपने पक्ष में कर रही है। इससे राय में सांप्रदायिक तनाव और बढ़ेगा व बंगाल हिंसा की आग में झुलसेगा। इससे आने वाले समय में सांप्रदायिक झड़पें भी बढ़ेंगी, जो राज्य की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राज्य में राजनीतिक हिंसा भले ही नई बात न हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस विरोधी पार्टियों पर जिस तरह हमले कर रही है, वह बंगाल के लिए एकदम नया है। 60-70 के दशक में अजय मुखर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बंगाल में कांग्रेस व वामदल के बीच चले हिंसक दौर में भी विपक्षी पार्टियों पर इस तरह हमले नहीं होते थे। अभी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस विपक्षी पार्टियों को पूरी तरह खत्म कर देने पर अमादा है। सत्ताधारी पार्टी जो कर रही है, उससे साफ है कि वह विपक्षी पार्टियों से खौफ खा रही है। लेकिन, राजनीतिक लड़ाइयां लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। ममता बनर्जी तानाशाह बनकर एक तरफ विपक्षी पार्टियों पर हमले करवा रही हैं और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक फ्रंट भी तैयार करना चाहती हैं। ऐसे में उन पर यह सवाल उठेगा कि लोकतांत्रिक फ्रंट बनाने वाली ममता बनर्जी खुद कितनी लोकतांत्रिक हैं?

Scanned with CamScanner

बिना जमीन वाले किसानों की सुध किसे

अभिज्ञान प्रकाश

पिछले कई सालों में देश के अलग-अलग हिस्सों के दुर-दराज के गांव-देहात में जब मैं किसानों पर रिपोर्टिंग करने पहुंचा तो एक बात स्पष्ट थी कि केन्द्र और राज्य स्तर पर किसानों के लिए योजनाओं की कोई कमी नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर भी किसानों का इतना बुरा हाल क्यों है? उसका एक बड़ा पहलू इस बात से सामने आता है कि इन योजनाओं का लाभ उन किसानों तक नहीं पहुंच पाता है जो किसी और के लिए खेती कर रहा हो, जिसके पास खुद की जमीन नहीं हो और यही खेतिहर किसान सालों-साल खेती करता रह जाता है और हमेशा के लिए स्थानीय साहूकार के हाथ की कठपुतली बन जाता है। केन्द्रीय बजट को किसान की तरफ केन्द्रित किया गया है। लक्ष्य यह तय किया गया कि पांच साल में किसान की आमदनी दुगुनी की जाए। मेरा सवाल बेहद बुनियादी है कि यह कौन से किसान होंगे? बड़े किसान या वे जिनका नाम किसी दस्तावेज में है ही नहीं और सरकार की किसी योजना का लाभ उनको नहीं मिल पाता मसलन फसल बीमा या किसानों को मिलने वाला कर्ज।

Scanned with CamScanner

जबकि मैं यह भी मानता हूं कि किसी भी गांव का सिस्टम बहुत आसानी से सरपंच या पटवारी के जरिये बता सकता है कि उस गांव के कितने किसान खुद अपनी जमीन जोतते हैं और कितने दूसरों के लिए आज तक कोई ऐसा आकलन ढूंढ पाना मुश्किल है जो यह बता सके कि इन खेतिहर किसानों की संख्या कितनी बड़ी है और सरकारों की स्कीमों से इन्हें क्या फायदा मिला है। क्या यह सतही फायदा सिर्फ बड़े या छोटे जमींदार किसानों तक सीमित तो नहीं है? हम इस प्रजातंत्र में संघीय ढांचे की बात करते हैं। इसमें इस पैसे को सही किसानों तक पहुंचाने में राज्यों और केन्द्र की बड़ी भूमिका है लेकिन आज तक कोई ऐसा तरीका नहीं बन पाया जिससे स्पष्ट हो कि किसानों के हक की स्कीमें कब, कैसे और कहां तक उनके पास पहुंची, साथ में यह जानकारी सार्वजनिक हो औद देश के सामने रखी जाए।

मिसाल के तौर पर आज से ठीक एक साल पहले इसी मार्च के महीने में देश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों की फसल बे मौसम बारिश से बर्बाद हुई तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले से डेढ़ गुने मुआवजे का एलान किया था लेकिन तमाम जगहों से रिपोर्ट आई कि किसानों को महज कुछ रुपयों के चेक बांट दिए गए। क्या यह तस्वीर बदल पाएगी? क्या किसान अपनी मजबूरी के इस दर्द से उबर पाएगा? क्या किसान अपनी उपज बढ़ा सकेगा, पैसे की अपनी मजबूरी दूर करके क्या किसान साहूकार के सामने अपनी देनदारी कम कर सकेगा? क्या किसान अपनी उपज को पूरी और सही कीमत पा सकेगा? क्या किसान अपनी उपज की पूरी और सही कीमत पा सकेगा? कोई भी सरकार या नेता कभी किसान विरोधी नहीं होता लेकिन साथ में किसानों के मन की बात पूरी तरह समझ भी नहीं पाता। किसी भी बजट प्रस्ताव में जो किसानों के लिए पैसा तय होता है, यह आपका और हमारा ही पैसा होता है जिसका किसानों के पास जाने में किसी को ऐतराज नहीं लेकिन सही किसानों तक पहुंचना ये सिस्टम और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यह बात भी साफ है कि देश के अलग-अलग हिस्से, चाहे वह महाराष्ट्र में विदर्भ हो या उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड, बाहर की समस्याएं, मौसम और पानी की वजह से वैसी ही बनी हुई हैं, फिर भी सरकारें बड़े-बड़े पैकेजों की घोषणा के इलाकों के लिए न आकलन, न रिपोर्ट, न पैकेज की कमी है। कमी इस बात की है कि इन इलाकों में पैसे के बंटवारे का मूल्यांकन किसने किया और जवाबदेही किसकी तय हुई। कई जानकार मानते है कि कृषि प्रधान देश में हम कृषि संबंधी संकट से गुजर रहे हैं। इसमें नए तरीके आने की पहले से कहीं ज्यादा जरुरत है लेकिन मैं वापस उस मूल प्रश्न पर आ रहा हूं कि क्या हम सुधार के जरिये उस किसान को नहीं पहचान पाएंगे जो खेत में मजदुरी कर रहा है और प्राकृतिक आपदा का पहला असर उस पर होता है। राज्य और केन्द्र सरकारों को बैठकर इस किसान को पहचानना बहुत जरुरी है।

कृषि प्रधान देश में सरकारों की एक आदत सी बन गई है किसान को बेचारे के रूप में देखने की। जरुरत है कि उस को कभी भी कमजोरी न समझा जाए बल्कि ताकत समझा जाए। ये गहरी चिंता की बात है कि जब मेरी मुलाकात उनके परिवारों से हुई तो वे नहीं चाहते कि उनकी नई पीढ़ी किसानी करे। अगर उनके पास विकल्प होता है तो वे शहर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। इस कुछ मूल बातों पर ध्यान देना जरूरी है। देश के कई हिस्सों में शिक्षा का स्तर कमजोर है इसलिए किसानों द्वारा पूरी की जाने वाली कागजी कार्यवाही का सरल होना जरुरी है ताकि किसान सिस्टम को अपने करीब लाए, न कि उससे दूर भागे। एक गैर पढ़े-लिखे व्यक्ति के लिए सरकारी भाषा समझना मुश्किल हो जाता है और यहीं पर उस तंत्र की जरुरत है जो उन्हें सरल भाषा में सारी बातें समझाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी भी बजट की आवाज किसानों तक नहीं पहुंच पाएगी और बजट विज्ञापनों और नारों में ही फंस कर रह जाएगा।

समता न्यूज व्यूज फीचर्स

Scanned with CamScanner

अधिक कार्बन उत्सर्जन पर कड़ाई जरूरी

शब्बीर कादरी

जलवायु परिवर्तन इन दिनों गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में ज्वलंत मुददा बनकर विश्व के सभी देशों को चेता रहा है कि प्रकृति के संतुलन से छेड़छाड़ मानव द्वारा यदि, अब भी नही रोकी गई तो इस ग्रह से जीवन का लुप्त होना सुनिश्चित है। इसी तथ्य को सामने रखकर आज संसार के प्रमुख वैज्ञानिक और देश इस ग्रह और उसमें विद्यमान जीवन को बचाने की चिंता कर रहे है, जैसे-जैसे विकास चक्र पर जीवन आगे बढ़ता जाता है पर्यावर्णीय परिस्थितियां और अधिक संकटमय बनती जाती हैं। बढ़ते तापमान से पूरी दुनिया में त्राहि-त्राहि है। याद रहे पृथ्वी का औसत तापमान 18वीं शताब्दी के बाद से अब तक 0.6 डिग्री सेन्टीग्रेड तक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का मत है कि यदि तापमान वृद्धि की यही रफ्तार रही तो वर्ष 2100 तक यह 1.4 से 5.8 डिग्री सेन्टी. तक बढ़ जाएगा जो पिछले 10,000 वर्षों में किसी सदी में बढ़ा सबसे अधिक तापमान होगा। समुद्र का स्तर बीसवीं शताब्दी में औसतन 10 से 20 सें.मी. बढ़ चुका है और वर्ष 2100 तक इस स्तर के 9.58 से.मी. और बढ़ जाने की संभावना है। 2001 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन पर अन्तर सरकार पैनल की तीसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके पुख्ता प्रमाण है कि पिछले 20 वर्षों में तापमान केवल मानव गतिविधियों के कारण ही बढ़ा है। अतः सहज ही समझा जा सकता है कि पृथ्वी पर सन्निकट पर्यावरणीय संकट के लिए अगर कोई दोषी है तो वह केवल मानव ही है।

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अपने पहले भाषण में बान की मून ने कहा था, पर्यावरण में बदलाव भविष्य में युद्ध और संघर्ष की बड़ी वजहें बन सकते हैं। महासचिव ने विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाले अमेरिका से अपील की कि वह ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करे। श्री मून का मत है कि युद्ध में मानवता को जितना नुकसान होता है उतना ही जलवायु संकट और ग्लोबल वार्मिंग से होना है, उनके अनुसार अफ्रीका और छोटे द्वीपों पर रह रहे लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे अधिक प्रभावित होंगे, जबकि इसके लिए वे सबसे कम जिम्मेदार हैं, इसी परिदृष्य में सूखा और बाढ़

Scanned with CamScanner

की संख्या भी बढ़ सकती है जिससे संघर्ष की स्थिति भी उपज सकती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जलवायु परिवर्तन पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानवीय गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक समुद्र का जल स्तर तथा पृथ्वी का औसत तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा। श्री मून के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग पर क्योटो संधि की अवधि खत्म होने से पहले औद्योगिक देशों को वर्ष 2012 तक ग्रीनहाउस गैसों , विशेषकर कार्बन डाइ आक्साइड की मात्रा को अगले दस साल में पांच प्रतिशत के स्तर से नीचे लाना तय हुआ था जिस पर संतोषजनक कार्य नहीं हो सका है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक और हास्यास्पद है कि दुनियाभर में ग्रीनहाउस गैसों का चौथाई हिस्से से अधिक उत्सर्जित करने वाला देश अमेरिका ने अभी तक क्योटो संधी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

कनाडा स्थित मांट्रियल कॉकोर्डिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता डैमन मैथ्यू का कहना है कि किस देश ने क्लाइमेट चैंज में सबसे अधिक योगदान किया और वे कौन से देश हैं जो सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने के उपरांत भी इसकी सबसे अधिक कीमत चुका रहे हैं उनके शोध के अनुसार यदि आप आस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकसित देश में रहते हैं तो उत्सर्जन को घटाने के लिए धन के तौर पर कार्बन उत्सर्जन का आपका डेबिट क्रमशः 10,000 से 12,000 डॉलर तक बैठता है वहीं अगर आप ब्राजील या भारत जैसे देश से हैं जो आपका क्लाइमेट-क्रेडिट 2000 डॉलर तक बनता है। विश्व के सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन देशों में अमेरिका,रूस, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जहां क्रमशः 10825, 7680, 7280 11,600, 10825, 4240,10600 डॉलर प्रति व्यक्ति कार्बन डेबिटर हैं जबकि कम कार्बन उत्सर्जक देशों में जिनमें क्रमशः भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, फिलीपींस, नाईजीरिया इत्यादि जैसे कई देश हैं जो क्रमशः 2500, 3280 2640, 2020, 2640, 2680 डॉलर प्रति व्यक्ति कार्बन डेबिटर हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि विश्व के संचयी कार्बन ऋण या देनदारियों में अकेले अमेरिका का हिस्सा 40 प्रतिशत बनता है, कनाडा का चार प्रतिशत है जबकि आबादी के हिसाब से जिन देशों में कार्बन उत्सर्जन में कम योगदान रहा है उनमें भारत, चीन, पाकिस्तान, ब्राजील, नाईजीरिया जैसे देश हैं जो कुल क्लड क्रेडिट में 30 प्रतिशत से भी कम भागीदार माने जाते हैं। शोधकर्ता मैथ्यू का मत है कि वैश्विक कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था बनाने में 10 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत होगी जो उस भरपाई के लिए काफी होगा जिन देशों ने इस संदर्भ में अधिक हानि को झेला है। स्पष्ट है कि यूएनओं के हरित जलवायु कोष के लिए प्रस्तावित 10 बिलियन या 100 अरब डॉलर के आंकड़े को मैथ्यू ने बौना सिद्ध किया है। हस्यास्पद और चिंताजनक यह भी है कि अभी तक यूएनओ के इस कोष में विकसित देशों द्वारा केवल 10.2 बिलियन डॉलर ही जमा हो सके हैं आशा की जा रही है वर्ष 2020 तक 10 बिलियन डॉलर की रकम जमा हो सकेगी जो पीड़ित देशों की मदद में काम आ सकती है।

सत्य समाचार फीसर्च

Scanned with CamScanner

शहादत को सलाम : खुदीराम बोस

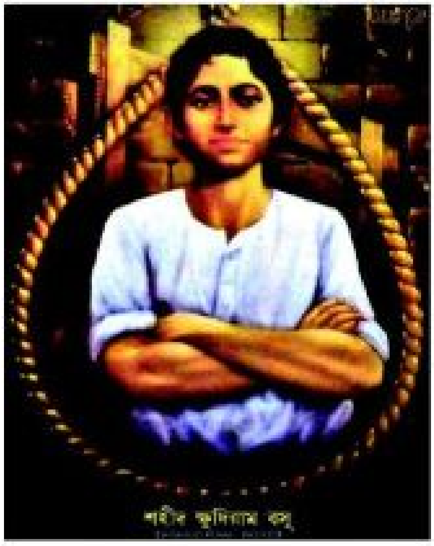

आर.एम.पी. सिंह

स्वतंत्रता की पौध का सिंचन शहीदों के रक्त से होता है। वह पौधा मजबुत होता है। भारतीय स्वतंत्रता की जड़ में शहीदों के रक्त की खाद है। इसलिये भारत की स्वतंत्रता को कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुँचा सकती। खुदीराम बोस भी उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से थे जिन्होंने भारत माता को गुलामी की जंजीर से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। केवल 19 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त, 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें फाँसी दी गई।

अमर शहीद खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर, 1889 को बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रैलोक्य बोस और माता का नाम लक्ष्मीप्रिया देवी था। उनका पालन-पोषण बहन के यहाँ हुआ। नौवीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गये। स्वदेशी आन्दोलन में शामिल हो गये। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु वह कैद से भाग निकले। लेकिन पुनः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन 16 मई, 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया।

खुदीराम बोस ने बंगाल के गवर्नर के विशेष ट्रेन पर भी हमला कर दिया परन्तु गवर्नर की जान बच गई। फिरंगियों से वे नफरत करते थे।

मुजफ्फरपुर के सेशन जज देशभक्तों को कड़ी सजा देता था। इसलिये श्री बोस उनसे नफरत करते थे। उन्होंने सेशन जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई। अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ वे मुजफ्फरपुर आयेऔर किंग्सफोर्डकी मुवमेंट की गोपनीय जानकारियाँ प्राप्त की। 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज के वाहन पर बम फेंक दिया। उस समय गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था। उसमें दो यूरोपीय महिला और एक बच्ची सवार थी। वे दोनों महिलायें व बच्ची मारी गई। इन दोनों को बेहद अफसोस हुआ कि किंग्सफोर्ड बच गया और अन्य मारे गये। जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया तो प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस पूसा रोड स्टेशन पर पकड़ लिये गये। तीन महीने तक सुनवाई के बाद 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। फाँसी के वक्त उन्होंने अपनी माँ से मिलने की इच्छा व्यक्त की और कहा - धुरि आयसे -फिर आऊँगा।

खुदीराम बोस की शहादत से संपूर्ण बिहार हिल उठा। स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गये।वे युवकों के प्रेरणास्रोत बनें। उस समय युवक ऐसी धोती पहनने लगे जिसपर खुदीराम लिखा होता था। जेल में वे गीता का अध्ययन करते थे। वह उनकी प्रिय पुस्तक थी।

खुदीराम बोस जीवन में ही आजाद भारत का सपना देखते थे। वे मित्रों से कहते थे - भारत ज्ञान का केन्द्र रहा है। यह महान देश है। फिर ये फिरंगी यहाँ क्यों राज कर रहे हैं। बड़ा होने पर मैं इन्हें देश से बाहर करूँगा।

खुदीराम बोस आज हमारे बीच नहीं हैं परन्तु उनका बलिदान युवकों के लिये प्रेरणास्रोत है। एक बार बचपन में खुदीराम एक मंदिर गये। वहाँ देखा बीमार लोग भगवान से स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बालक खुदीराम ने कहा - गुलामी से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। मुझे उसे भगाना है। वे वंदे मातरम व भारत माता की जय से अभिभूत रहते थे। वे आनंदमठ पुस्तक से प्रभावित थे और देश सेवा में उत्सर्ग करने का संकल्प लिया था। किंग्सफोर्ड जब कलकत्ता में प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट था, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकर्ताओं को निष्ठुरतापूर्वक सजा देता था। खुदीराम वहीं से चिढ़े थे और उसको समाप्त करना चाहते थे। बम फेंकने के बाद वे वहाँ से भाग निकले। एक दुकान पर चाय मुढ़ी खा रहे थे। वहाँ लोगों में चर्चा थी कि किंग्सफोर्ड बच गया, दो महिलायें व एक बच्ची की मौत हो गई। यह सुनकर खुदीराम - अचानक बोल उठे - किंग्सफोर्ड नहीं मरा!! खुदीराम वहीं गिरफ्तार कर लिये गये। सुनवाई के दौरान जेल में उनका वजन बढ़ गया था। उन्होंने जज से कहा था - मुझे केवल इतना सा अफसोस है कि किंग्सफोर्ड को सजा नहीं मिली। और वंदे मातरम के साथ वे फांसी पर झूल गये।

Scanned with CamScanner

आज सड़कों पर

आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख,
पर अन्धेरा देख तू आकाश के तारे न देख ।

एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ,
आज अपने बाज़ुओं को देख पतवारें न देख ।

अब यकीनन ठोस है धरती हक़ीक़त की तरह,
यह हक़ीक़त देख लेकिन ख़ौफ़ के मारे न देख ।

वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे,
कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें न देख ।

ये धुन्धलका है नज़र का तू महज़ मायूस है,
रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख ।

राख़ कितनी राख़ है, चारों तरफ बिख़री हुई,
राख़ में चिनगारियाँ ही देख अंगारे न देख ।

धर्म

तेज़ी से एक दर्द
मन में जागा
मैंने पी लिया,
छोटी सी एक ख़ुशी
अंधेरों में आई
मैंने उसको फैला दिया,
मुझको सन्तोष हुआ
और लगा –
हर छोटे को
बड़ा करना धर्म है ।

दुष्यंत कुमार त्यागी

Scanned with CamScanner

समूहों ने दी पहचान

आजीविका गतिविधियों से जुड़कर हुआ सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण

आर.एस.मीणा

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2012 से ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिये स्व-सहायता समूह बनाकर उनके संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मिशन द्वारा प्रदेश में अब-तक समस्त जिलों के 43 हजार 781 ग्रामों में 3,08,676 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से 34 लाख 78 हजार परिवारों को जोड़ा जा चुका है।

मिशन का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित कर उन्हें सशक्त बनाने हेतु प्रशिक्षित कर सहयोगात्मक मार्गदर्शन करना एवं समूह सदस्यों के परिवारों को रूचि अनुसार उपयोगी स्व-रोजगार एवं कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की आजीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत निर्धन श्रेणी के परिवारों के इन समूहों को मिशन द्वारा चीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि आपदा कोष तथा बैंक लिंकेज के रूप में वित्तीय सहयोग किया जा रहा है। इस राशि से उनकी छोटी

Scanned with CamScanner

बड़ी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जिससे वह साहूकारों के कर्जजाल से बच जाते हैं।

मिशन द्वारा दिये जा रहे लगातार प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय सहयोग एवं सहयोगात्मक मार्गदर्शन से लाखों परिवारों की निर्धनता दूर हो गई है। प्रशिक्षणों का ही परिणाम है कि समूह सदस्यों के अन्दर गरीबी से उबरने की दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप वह आगे बढ़कर पात्रता आनुसार अपने हक, अधिकार न केवल समझने लगे हैं बल्कि प्राप्त करने लगे हैं।

मिशन के प्रयासों से ग्रामीण निर्धन परिवारों के जीवन में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। इनमें सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण प्रमुख रूप से देखा जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन परिवारों में महिलाओं की आय मूलक गतिविधियों करने के अवसर नहीं मिलते थे, उनका जीवन केवल चूल्हे-चौके व घर की चार दीवारी तक ही सीमित रह जाता था। घर के संचालन, आय-व्यय आदि सहित अन्य मुद्दों पर निर्णय में पुरूषों का एकाधिकार था, यहाँ तक कि महिलाओं के आने-जाने, उठने-बैठने, पहनने-ओढ़ने, खाने-पीने आदि जैसे व्यक्तिगत मुद्दों पर भी उनकी राय लेना मुनासिब नहीं समझा जाता था, बल्कि सब कुछ एकतरफा उनपर थोप दिया जाता था। कभी परंपरा तो कभी संस्कार मर्यादा के नाम पर महिलाओं के पास इन्हें ढोने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। उनकी अपनी कोई पहचान इच्छा-अनिच्छा, सहमति-असहमति नहीं होती थी। घर के संचालन एवं खेती बाड़ी तथा व्यवसायिक कार्यो में महिलाएँ तो जैसे सपनों की बातें हों।

मिशन के समूहों से जुड़कर महिलाओं को जो अवसर मिला उससे उन्होंने अपनी काबलियत को सिद्ध कर अपनी अलग पहचान बनाई। आज प्रदेश में समूहों से जुड़े 12 लाख 31 हजार से अधिक परिवार कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़े हैं जबकि 3 लाख 85 हजार से अधिक परिवार गैर कृषि आधारित लघु उद्यम आजीविका गतिविधियों से जुड़कर काम कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के लिये एक वर्ष में रू.1400 करोड़ बैंक ऋण समूहों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत भी 10 हजार रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह राशि मिलने से समूहों की गतिविधियों में गति बढ़ गई है।

गैर आय मूलक नगण्य घरेलू कामों के अलावा अब समूह सदस्य महिलाएँ अपने

Scanned with CamScanner

परिवार के साथ-साथ गांव एवं सामुदायिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय देती हैं। उनके अन्दर आई जागरूकता के कारण न केवल घर में बल्कि गांव व क्षेत्र में भी उनके सम्मान में बढ़ोतरी है। समूहों, ग्राम संगठनों, संकुल स्तरीय संघो की नियमित बैठकों में भागीदारी करने से उनकी समझ व सक्रियता बढ़ गई है उनकी कार्यशैली में निखार एवं आत्म विश्वास में बढ़ोतरी हुई है। समूहों में सिखाये गये 13 सूत्रों ने उन्हें मूल मंत्र दे दिया जिससे वे निरंतर आगे बढती जा रही हैं। समूहों की बैठक में नियमित बचत लेन-देन, ऋण वापसी तथा दस्तावेजी करण, बैंकों में आने-जाने से उनके अंदर वित्तीय साक्षरता, व्यवसायिक प्रबंधन की क्षमता विकसित हो गई। इसी का परिणाम है कि घूंघट में रहने वाली शर्मीले स्वभाव की ग्रामीण महिला आज अपनी यह पहचान बदलकर बड़ी-बड़ी सभाओं में मंच से लाखों की भीड के सामने निर्भीक होकर अपने विचार व्यक्त करती है।

इस पूरे काम में एक खास बात यह है कि महिलाओं का अनपढ़ होना बाधक नहीं बना और वे सदियों पुरानी रूढियों को तोड़कर अपने गुमनाम जीवन से उठकर समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका में पहुंचने में कामयाब हो गई। आज उनकी पहचान केवल किसी की पत्नी, बहू या मां के रूप में ही नहीं है बल्कि अब वे समूहों संगठनों के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के रूप में जानी जाती हैं। घरों में अब नजारे उल्टे हैं, सास, ससुर पति सहित सभी एक स्वर में इनका नेतृत्व सहज स्वीकार करते देखे जा सकते हैं। इन्होंने इस सत्ता परिवर्तन के लिये कोई हिंसक लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि अपनी काबलियत के दम पर सत्ता स्वीकार करने के लिये अपने परिजनों को तथा समुदाय को मजबूर कर दिया।

आज पत्नी से पूछकर पति बाहर जाता है घर में फसल, पढ़ाई लिखाई, खरीद बिी, आदि निर्णय महिलाओं की राय पर ही लिये जाते हैं।

सामुदायिक विकास के क्षेत्र में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले की तुलना में ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना, पात्रता अनुसार स्वास्थ्य, पोषण, षिक्षा आदि के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक मुद्दों पर भी जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन देखा जा सकता है। घर-घर में पोषण वाटिका लगाकर अपना, अपने परिवार का तथा अपने गांव में

Scanned with CamScanner

कुपोषण दूर करने के प्रयास देखे जा सकते हैं।

समूह सदस्यों के अन्य व्यवहार परिवर्तनों में एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन है नगद रहित व्यवहार, समूहों का समस्त लेन-देन चैक के माध्यम से ही होता है या फिर बैंक सखियों द्वारा ई-ट्रांजिक्शन भी कराया जाता है। इस कारण आर्थिक धोखाधड़ी की संभावनाएँ कम हो गई हैं।

परंपरागत आय के साधन कृषि-पशुपालन के साथ-साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिये सिलाई, दुकान, साबुन, अगरबत्ती निर्माण, आदि सहित 103 प्रकार की लघु उद्यम गतिविधियां रूचि अनुसार की जा रही हैं जिस कारण संवहनीय आजीविका के अवसर मिलने से इनकी आय में उत्तरोत्तर वृद्धि निरंतर हो रही है। प्रदेश में 2 लाख से अधिक महिलाएँ ऐसी हैं जो न्यूनतम 10 हजार रू. मासिक आय अर्जित कर रही हैं।

समूहों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलने से जो नई पहचान मिली उसकी वजह से विभिन्न राजनैतिक पदों पर भी समूह सदस्य निर्वाचित हुई हैं। पंच-सरपंच से लेकर जपनद जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधायक व राय सभा सदस्य जैसे पदों तक भी पहुंची हैं। इसके अलावा विभिन्न समितियों में भी महत्वपूर्ण पद मिले हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में घूंघट की ओट में चूल्हे चौके तक सीमित रहकर गुमनाम जिंदगी जीने वाली महिलाएँ अपने परिवार गांव, जिले की पहचान व शान बन गई।

समुदाय के बीच समूह की अवधारणा के प्रचार-प्रसार, क्षमता वर्धन, बैंक संयोजन, समूहों की आय अर्जन गतिविधियों में सहयोग आदि कार्य के लिये समूह सदस्यों में से ही सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों का चिन्हांकन एवं प्रशिक्षण किया गया। सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति सामुदायिक संस्थाओं के स्थाई रूप से सषक्तिकरण में सहभागी बने, साथ ही इस कार्य से उन्हें अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है।

मिशन द्वारा लगभग 6000 महिलाओं को कम लागत कृषि एवं जैविक खेती पर प्रशिक्षित किया गया। इन्होंने मास्टर कृषि सी.आर.पी. के रूप में न केवल अपने घर, गांव जिला प्रदेश, बल्कि अन्य रायों जैसे-हरियाणा, उत्तरप्रदेश व पंजाब में भी सेवाएँ देकर अपनी अलग पहचान बनाई है। सामाजिक सषक्तिकरण के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी महिलाओं ने नये आयाम स्थापित किये हैं। समूहों से जुड़े कई ऐसे परिवार भी हैं जिनकी मासिक आय 50 हजार रूपये तक है। लाखों की संख्या में महिलाओं ने पुराने जीर्ण-शीर्ण घरों की जगह अपने पक्के मकान, दुकान आदि बनवा लिये, कृषि भूमि खरीदी है तथा साहूकारों के कर्ज जाल से मुक्ति पाकर नये जीवन की शुरूआत की है। बदलाव की नजीर देखें तो अकेले अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ क्षेत्र में 19 गांवों के 26 समूहों के 76 सदस्यों ने 26 लाख से अधिक रूपये से गिरवी रखी 176 एकड़ जमीन साहूकारों के कर्जे से वर्ष 2019 में मुक्त कराई। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण विभिन्न जिलों में हैं। समूह सदस्यों की आय में वृद्धि होने से आर्थिक रूप से आत्म निर्भर होने पर उन्होंने स्वयं की अपूर्ण पढ़ाई फिर से शुरू कर व्यवसायिक कोर्स जैसे बी.एस.डब्ल्यू. एम.एस.डब्ल्यू. भी किया है। साथ ही बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दो पहिया, चारपहिया वाहन, कृषि यंत्र आदि खरीदे हैं।

स्वयं का आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण करने के साथ-साथ अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकना, घरेलू हिंसा के विरूद्ध आवाज उठाना, नशा मुक्ति कराना, सामुदायिक विकास के कार्यों की निगरानी, गांव के बेरोजगार युवक युवतियों को रूचि अनुसार रोजगार, स्व-रोजगार प्रशिक्षण दिलाने जैसे काम विभिन्न उप-समितियों के माध्यम से महिलाएँ कर रही हैं। स्व-सहायता समूहों में मिले अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए अपनी क्षमता के अनुसार काम करके प्रतिभा प्रदर्शन से मिली अलग पहचान की बदौलत ही महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक एवं सामुदायिक सत्ता पर अपना वर्चस्व कायम किया है, जो कि महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के जीवंत उदाहरण हैं।

Scanned with CamScanner

URBANISATION BEHIND FLOODS

SHAIFALI VAIBHAV

Rains the most awaited season of years from the perspective of farmers. In urbanized lands does the rains have same value? The big and metro cities of country get flooded in just two or three showers, it is so because of the unprecedented rainfall, unplanned urbanisation and lack of preparedness. According to a study these are the only common reasons along with the intense rainfall event which caused floods in the areas such as Jammu & Kashmir, Chennai, Mumbai, etc.

Looking at the case of Jammu and Kashmir, year 2014, in the last 100 years, more than 50 per cent of the lakes, ponds and wetlands of Srinagar have been encroached upon for constructing buildings and roads. The banks of the Jhelum river have been taken over in a similar manner, vastly reducing the river's drainage capacity. Naturally, these areas have suffered the most.

Similarly what happened in Chennai in December 2015 also resembles the Kashmir condition. When the water level was crossing the normal limits in residential areas, the drainage system measurably failed to pass the water. The drainage systems were blocked due to excessive dumping of garbage as well as the administration's failure to

Scanned with CamScanner

ensure timely desilting. Hence water could not find a way to flow. The failure of drainage system in Chennai and other parts of Tamil Nadu made the situation worst. Besides that, encroachments was seen on Cooum River, Adyar River and Buckingham Canal, which serve as the main rain water drain for the city. These encroachments were not slum not slum dwellings but concrete structures directly affecting the flow of the canal. Also, the increasing urbanization has lead to the lack of wetland, which acts as a sponge, soaking up rain water, played vital role in floods. The wetlands have been developed into commercial areas and thus a very small part of wetlands still remain. Hence, rain water runoff has nowhere to go and settles instead onto roads, causing flooding. Mismanagement and violation of norms in urban planning have caused such severe flooding.

Another metro city much prone to such floods is Mumbai. Owing to massive concretisation of roads and unplanned constructions that have flattened the natural topography, almost 90 to 100 per cent of the rainwater in the city drains off into the stormwater drains instead of being absorbed into the ground. In Mumbai, only the

city area has a semblance of an efficient drainage system built over a century ago by the British; the suburbs have to contend with open drains layered with debris, garbage and sewage. Kapil

Scanned with CamScanner

Gupta, urban flooding expert from IIT Mumbai, says the problem is of effective water management considering that Chennai receives ample rainfall, 1,200 mm annually, from both the Southwest and Northeast monsoon. Gupta was the convenor of an expert panel, under the National Disaster Management Authority, set up in the aftermath of the Mumbai floods. The panel came up with India's first-ever urban flooding report that stressed on the need to recognise urban flooding as a distinct category that requires "to be treated holistically in a multi-disciplinary manner". Mumbai had upped its ante on the flood prediction and warning system following a report by a state fact-finding committee under MadhavChitale, set up after the floods. It has installed 60 automatic rain gauges, prepared contour maps, identified chronic flooding spots and built a state-of-the-art disaster control room that transmits real-time data to all. However, Mumbai has failed to deliver on city planning and infrastructure. Builders have been allowed to go ahead with their diluted interpretation of stringent Coastal Regulation Zones while there are plans afoot to allow private developers to construct 'affordable housing' on 5,500 acres of salt-pan lands. Based on recommendations of the Chitale committee, the municipal corporation took up a project to double the water

Scanned with CamScanner

receding capacity of the drains to 50 mm per hour by 2011. It is now staring at a 2019 deadline and a two-fold cost escalation.

HYDROLOGIC EFFECTS OF URBAN DEVELOPMENT

Streams are fed by runoff from rainfall and snowmelt moving as overland or subsurface flow. Floods occur when large volumes of runoff flow quickly into streams and rivers. The peak discharge of a flood is influenced by many factors, including the intensity and duration of storms and snowmelt, the topography and geology of stream basins, vegetation, and the hydrologic conditions preceding storm and snowmelt events.

Land use and other human activities also influence the peak discharge of floods by modifying how rainfall and snowmelt are stored on and run off the land surface into streams. In undeveloped areas such as forests and grasslands, rainfall and snowmelt collect and are stored on vegetation, in the soil column, or in surface depressions. When this storage capacity is filled, runoff flows slowly through soil as subsurface flow. In contrast, urban areas, where much of the land surface is covered by roads and buildings, have less capacity to store rainfall and snowmelt. Construction of roads and buildings often involves removing vegetation, soil, and depressions from the land surface. The permeable soil is

Scanned with CamScanner

replaced by impermeable surfaces such as roads, roofs, parking lots, and sidewalks that store little water, reduce infiltration of water into the ground, and accelerate runoff to ditches and streams. Even in suburban areas, where lawns and other permeable landscaping may be common, rainfall and snowmelt can saturate thin soils and produce overland flow, which runs off quickly. Dense networks of ditches and culverts in cities reduce the distance that runoff must travel overland or through subsurface flow paths to reach streams and rivers. Once water enters a drainage network, it flows faster than either overland or subsurface flow.

With less storage capacity for water in urban basins and more rapid runoff, urban streams rise more quickly during storms and have higher peak discharge rates than do rural streams. In addition, the total volume of water discharged during a flood tends to be larger for urban streams than for rural streams.

REDUCING FLOOD HAZARDS IN URBAN AREAS

There are many approaches for reducing flood hazards in basins under development. Areas identified as flood-prone can be used for parks and

Scanned with CamScanner

playgrounds that can tolerate occasional flooding. Buildings and bridges can be elevated, protected with floodwalls and levees, or designed to withstand temporary inundation. Drainage systems can further be expanded to increase their capacity for detaining and conveying high streamflows; for example, by using rooftops and parking lots to store water. Techniques that promote infiltration and storage of water in the soil column, such as infiltration trenches, permeable pavements, soil amendments, and reducing impermeable surfaces can also be incorporated into new and existing residential and commercial developments to reduce runoff from these areas.

In response to frequent flooding along the small rivers in various urban areas, the local community can integrate many of these approaches into a single plan for flood protection that is expected to reduce flood damage while helping to restore the river ecosystem. The plan involves bridge reconstruction, levee setbacks, a floodwall, moving of vulnerable structures, detention basins, larger stormwater conveyances, and a high-flow bypass channel.

Urbanization generally increases the size and frequency of floods and may expose communities to increasing flood hazards. Current streamflow information provides a scientific foundation for flood planning and management in urban areas. Because flood hazard maps based on streamflow data from a few decades ago may no longer be accurate today, floodplain managers need new peak streamflow data to update flood frequency analyses and flood maps in areas with recent urbanization. Streamflow-gaging stations provide a continuous record of streamflow that can be used in the design of new urban infrastructure including roads, bridges, culverts, channels, and detention structures. Stormwater managers can use streamflow information in combination with rainfall records to evaluate innovative solutions for reducing runoff from urban areas. Real-time streamflow-gaging stations, which make streamflow and rainfall data available via the internet and other communications networks as they are recorded, offer multiple benefits in urban watersheds. In particular, they provide flood managers with information that can guide flood control operations and emergency actions such as evacuations and road closures.

Scanned with CamScanner

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

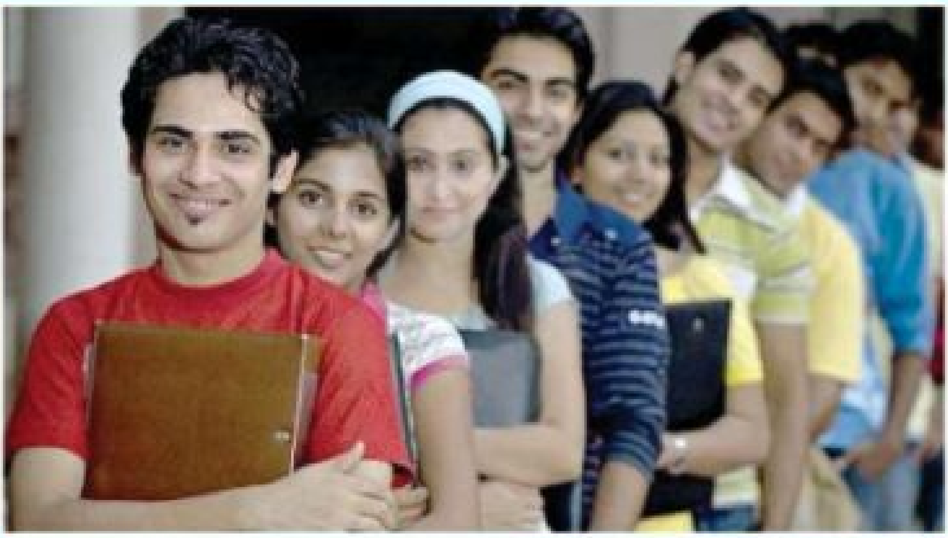

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) 9826064596

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

Scanned with CamScanner